दिनमान | तापमान

सूर्योदय 5.16 | सूर्यास्त 5.56 | अधिकतम 37° | न्यूनतम 27°

निष्पक्ष, निडर एवं सशक्त राष्ट्रीय दैनिक

युवा शक्ति

वर्ष 18, अंक 300 पृष्ठ 8

कोलकाता, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026

वैशाख, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, वि.सं. 2083

मूल्य: ₹3

कोलकाता संस्करण

www.yuvashaktinews.com

लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा

यह अवसर न जाने दें, इस मंथन से अमृत निकलेगा : पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक यानी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा के दौरान इसे भारत की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव बताया. पीएम ने कहा कि यह विधेयक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लोकतंत्र को और अधिक समृद्ध बनाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा और यह मंथन देश की दिशा और दशा तय करेगा. पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है. यह 20-25 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, समय-समय पर इसमें सुधार होते रहते. सदन के सभी साथियों को यह अवसर मिला है. पीएम ने परिसीमन पर दक्षिण भारत के हर राज्य का भ्रम दूर किया और कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं, उस समय समाज की मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है. मैं समझता हूं कि संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं. जरूरत महसूस हुई होती तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते. हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहे हैं. हमारी हजार वर्ष की विकास यात्रा रही है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक जीवन में जो लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25 से 30 वर्ष में ग्रासरूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर महिलाएं लीडर बन चुकी हैं. अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33 फीसदी का सामर्थ्य नहीं है, बल्कि वे आपके फैसलों को भी प्रभावित करने वाली हैं. इसलिए जो आज विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

बंगाल में भाजपा का 'युवाशक्ति भरोसा' कार्ड जारी

बेरोजगार युवाओं को 3000 मासिक भत्ता देने का वादा

- 'मातृशक्ति भरोसा' कार्ड भी जारी कर चुकी है भाजपा
- टीएमसी ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया

कोलकाता: बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपना एक और मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए 'युवाशक्ति भरोसा' कार्ड लांच किया है. इसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है. गुरुवार को दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लियेंडर पेस और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की उपस्थिति में यह कार्ड जारी किया गया. यहां बताते चलें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले दसवीं पास युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पांच वर्ष रोजागर मिलने तक भत्ता देना शुरू किया है. उसी के जवाब में भाजपा ने युवाओं को भरोसा दिलाने के लिए यह कार्ड जारी किया है, जो घर-घर पहुंचाया जाएगा.

इस अवसर पर लियेंडर पेस ने कहा कि बंगाल से उद्योगों और युवाओं का पलायन चिंताजनक है. कोलकाता जैसे महानगर को चुंबक की तरह होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे, लेकिन यहां से प्रतिभा बाहर जा रही है. वहीं विजेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल के लोग 'बासी मछली' और 'बासी सरकार' पसंद नहीं करते, इसलिए अब बदलाव का समय है. भाजपा का कहना है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. पार्टी इसे राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक व्यापक दृष्टि का हिस्सा बता रही है.भाजपा इससे पहले बुधवार को महिलाओं के लिए 'मातृशक्ति भरोसा' कार्ड भी जारी कर चुकी है. इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के युवाशक्ति कार्ड व 'मातृ शक्ति भरोसा कार्ड' के लॉन्च और वितरण के संबंध में भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.

बंगाल में सीएम योगी ने चुनावी सभा में कहा

भाजपा आयी तो सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे, माफिया व मौलाना

कोलकाता: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को टीएमसी सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि 15 वर्षों के शासन में उसने बंगाल को आतंक, माफिया राज, कटमनी, भ्रष्टाचार व अराजकता का अड्डा बनाकर रख दिया है. बंगाल के चुनावी रण में दूसरी बार उतरे योगी ने तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के क्रम में मतदाताओं से बेखौफ होकर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडे, माफिया क्या कह रहे हैं या कोई मौलाना क्या बक रहा है, आप किसी से भयभीत न होइए.

डबल इंजन की भाजपा सरकार आने दीजिए, गुंडे, माफिया व मौलाना आपकी चाटुकारिता करते और बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे. अपराधियों व माफियाओं का इलाज केवल भाजपा की डबल इंजन की सरकार के पास है. योगी ने पश्चिम बर्द्धमान जिले के आसनसोल के पास बाराबनी और बीरभूम जिले के रामपुरहाट व बोलपुर में तीन जनसभाओं को संबोधित किया. योगी ने कहा कि जो बंगाल कभी शिक्षा व कल-कारखानों का केंद्र और भारत की अर्थव्यवस्था का लीडर था, वह आज माफिया की चपेट में है. बंगाल बालू माफिया, कोयला माफिया, लैंड माफिया, मवेशी माफिया और सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफियाओं के चंगुल में है. टीएमसी ने बंगाल को क्राइम कैपिटल में बदल दिया है. टीएमसी आतंक, माफिया व भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है. वो टीएमसी अब नहीं चाहिए. इस बार टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि भाजपा गारंटी देती है कि बंगाल में सरकार बनने पर दंगा नहीं होगा और न कर्फ्यू लगेगा. गोमाता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस, फिर वामपंथियों और 15 वर्ष से टीएमसी ने बंगाल के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है. बंगाल कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देश को दिशा देता था, लेकिन टीएमसी ने इसे क्राइम कैपिटल बना दिया है. इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी-बहनों के सामने भय का माहौल पैदा किया है. इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं.

आजादी के बाद बंगाल विकास के पथ पर आगे चल रहा था. देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था. बंगाल की तूती बोलती थी.

रैली में ममता ने 'डराया' वे बम धमाका करेंगे व इल्जाम किसी और पर लगायेंगे

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दीनहाटा की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी (भाजपा की) योजना है कि वे एनआईए को बुलाएंगे, बम धमाका करेंगे और फिर इसका इल्जाम किसी और पर लगा देंगे. वे बाहर से कुछ लोगों को लाएंगे, आप पर आरोप लगाएंगे और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे.

बस कुछ ही दिन बाकी हैं. धैर्य रखें, वोटर लिस्टप में अपना नाम दर्ज कराएं और किसी भी तरह की परेशानी में न पड़ें. मैं आपसे अपील करती हूं; वे गड़बड़ी पैदा करके वोट चुरा लेंगे. जरूरत पड़ने पर आप रात में भी उन पर नजर रखें.

अभिषेक ने भाजपा पर लगाया लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप

झाड़ग्राम: तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और कुड़माली भाषा की लंबित मान्यता को लेकर भाजपा पर हमला किया. अभिषेक ने झाड़ग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. भाजपा द्वारा उसके घोषणा-पत्र में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर यूसीसी लागू करने का वादा किए जाने का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि यह आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों और प्रथाओं को दरकिनार करते हुए उनपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. उन्होंने भाजपा पर लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने केंद्र सरकार पर झाड़ग्राम जिले सहित राज्य के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने दो महीने पहले केंद्र को पत्र लिखकर इस भाषा को शामिल करने की मांग की थी, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. भाजपा ने बंगाल के लिए अपने घोषणा-पत्र में कुड़माली और राजबंशी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया है. अभिषेक बनर्जी ने महिलाओं को 3,000 रुपये की प्रस्तावित मासिक सहायता के लिए फॉर्म भरने के खिलाफ आगाह किया, और आरोप लगाया कि इसी तरह के वादों के बावजूद भाजपा शासित किसी भी राज्य ने ऐसी योजना लागू नहीं की है.

बंगाल में घुसपैठियों का स्वागत करती हैं ममता : हिमंत विश्वशर्मा

कालचिनी/कूचबिहार : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि जहां उनके राज्य और त्रिपुरा में भाजपा सरकारें बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति नहीं देती हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल में उनका स्वागत करती हैं. असम की सीमा से लगे अलीपुरद्वार जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शर्मा ने यह भी दावा किया कि तृणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की अनुमति नहीं देती है. उन्होंने आरोप लगाया, असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकारें बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में उनका स्वागत करती हैं. शर्मा ने कहा कि अवैध आप्रवासन के कारण पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, और दावा किया कि राज्य में हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है. असम के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा पूर्वोत्तर राज्य में निश्चित रूप से जीतेगी और चार मई को चुनाव परिणाम घोषित होने पर 126 सदस्यीय (असम) विधानसभा में शतक बनाएगी. असम में विधानसभा चुनाव नौ अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे और मतगणना चार मई को होगी. उन्होंने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान असम में बांग्लादेशी मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई थी, लेकिन राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद परिदृश्य बदल गया. शर्मा ने ममता बनर्जी सरकार पर बंगाल और असम में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि को अस्वीकार करने के लिए चाय बागान मालिकों के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया.

3 बार के विधायक अब्दुर रज्ज़ाक ने तृणमूल छोड़ी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले की जलांगी विधानसभा सीट से तीन बार के अनुभवी टीएमसी विधायक अब्दुर रज्जाक ने गुरुवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा की. उन्होंने यह फैसला इस बार टिकट न दिए जाने की नाराजगी के चलते किया. अब्दुर रज्जाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए टीएमसी नेतृत्व पर तीखा हमला भी बोला. उन्होंने दावा किया कि इस बार टीएमसी के उम्मीदवार न केवल जलांगी में, बल्कि आसपास की डोमकल और रानीनगर विधानसभा सीटों पर भी हारेंगे. अब्दुर रज्जाक ने कहा कि उन्हें फिर टिकट इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि वे पार्टी को एक बड़ी रकम नहीं दे पाए. रज्जाक ने कहा कि फिलहाल पार्टी के भीतर ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है.

मतदान से दो दिन पहले भी मिली क्लीन चिट तो दे पाएंगे वोट

21 अप्रैल व 27 अप्रैल तक ट्रिब्युनल के निपटारे वाले वोटरों को राहत

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कोर्ट के आदेश से मतदान अधिकार और सूची अपडेट को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है. पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव से ठीक पहले तक अपीलीय ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा चुनाव से दो दिन पहले तक मंजूर किए जाएंगे, उन्हें आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति होगी. कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 21 अप्रैल या 27 अप्रैल 2026 तक अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए एक पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए, ताकि योग्य नागरिकों को मतदान से वंचित न होना पड़े. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की अपील लंबित है, उन्हें केवल इसी आधार पर मतदान का अधिकार वापस नहीं दिया जाएगा. यानी अपील प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक होगा. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जिन मामलों में अपीलीय ट्रिब्युनल 21 अप्रैल (जहां चुनाव 23 अप्रैल को है) या 27 अप्रैल (जहां चुनाव 29 अप्रैल को है) तक अपील का निपटारा करके उन्हें मंजूर कर लेती हैं उन मामलों में मतदान का अधिकार देने के लिए पुनरीक्षित मतदाता सूची निकाली जाएगी.अपील लंबित रहने से मतदान का हक नहीं हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट से स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से बाहर किये गए लोगों को अपीलीय ट्रिब्युनल के समक्ष सिर्फ अपील लंबित रहने से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करना चाहिए.

अफसरों के तबादले रोकने की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. यह तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला रखा जाएगा.

भाजपा पश्चिम बंगाल में 'डबल सेंचुरी' पार करेगी : हिमंत बिस्वा सरमा

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल में भाजपा डबल सेंचुरी यानी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने यह बातें कही। वह फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी दुर्गा मुर्मू के समर्थन में खोरीबाड़ी के बतासी पीएसए मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राज्य की सत्तारूढ़ सरकार तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असम चुनाव में व्यस्त रहने के कारण वे पहले नहीं आ सके, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पार्टी के निर्देश पर प्रचार के लिए यहां पहुंचे है।उन्होंने राज्य सरकार को माफिया, मनी और मर्डर की सरकार बताते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।असम

और बंगाल की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि असम में चाय बागान मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलती है, जबकि बंगाल में कम है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने पर लगभग पांच लाख नौकरियां दी जाएंगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही है कि भाजपा के सत्ता में आने पर मछली-मांस पर रोक लग जाएगी।

उन्होंने कहा कि असम में भाजपा सरकार होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा खुली होने के कारण जनसंख्या संतुलन बदल रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की तृणमूल सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। भाजपा सरकार आने पर इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।-

मतदाताओं में भरोसा बढ़ाने मैदान में उतरे डीएम और एसपी

सिलीगुड़ी : मतदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक बूथ-बूथ पर पहुंच रहे हैं। आगामी 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने वाला है। इसी बीच, आठ अप्रैल को नक्सलबाड़ी में तृणमूल और बीजेपी के बीच झड़प की घटना हुई थी।इसी को देखते हुए नक्सलबाड़ी के रायपाड़ा इलाके में लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए बुधवार रात दार्जिलिंग के जिलाधिकारी हरिशंकर पनिकर और जिला पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा झारखंडिया पहुंचे। उन्होंने नक्सलबाड़ी के रायपाड़ा और नंद प्रसाद बालिका विद्यालय के बूथों का निरीक्षण किया और आम लोगों को आश्वस्त किया।

रायपुर विधानसभा में चतुष्कोणीय मुकाबला, कुड़मी वोट बने निर्णायक

बांकुड़ा : जिले की रायपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला जबरदस्त हो गया है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जबकि वाममोर्चा और कांग्रेस भी चुनावी लड़ाई में मौजूद हैं। क्षेत्र में कुड़मी समुदाय के मतदाताओं की बड़ी संख्या होने के कारण चुनावी गणित और जटिल हो गया है। आदिवासी कुड़मी समाज ने इस बार भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है, हालांकि इससे सभी कुड़मी वोट भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे, यह निश्चित नहीं माना जा रहा है।जंगलमहल क्षेत्र की रायपुर विधानसभा सीट कभी वाममोर्चा का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। वर्ष 2011 में सत्ता परिवर्तन के समय भी यहां से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता स्वर्गीय उपेन किस्कू विजयी हुए थे। इसके बाद 2016 और 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की। इस बार तृणमूल ने मौजूदा विधायक मृत्युंजय मुर्मू की जगह ठाकुरमणि सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने क्षेत्रमोहन हांसदा को टिकट दिया है, जबकि माकपा की ओर से रामचंद्र मांडी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के टिकट पर शुभ्रा हेम्ब्रम मुर्मू चुनाव लड़ रही हैं।पूर्व विधायक मृत्युंजय मुर्मू का कहना है कि उन्होंने विधायक निधि का पूरा उपयोग क्षेत्र के विकास में किया है। पिछले पांच वर्षों में कई स्कूलों में बाउंड्री वॉल का निर्माण, बालिका विद्यालयों और छात्रावासों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तथा ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ ही कई स्थानों पर हाईमास्ट लाइट लगाई गई और खेल मैदानों का नवीनीकरण किया गया।तृणमूल उम्मीदवार ठाकुरमणि सोरेन का दावा है कि राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को लाभ मिला है और इसी विकास के आधार पर उनकी जीत तय है।दूसरी ओर, भाजपा उम्मीदवार क्षेत्रमोहन हांसदा का आरोप है कि तृणमूल शासन में क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। उनका कहना है कि वास्तविक विकास के लिए लोग इस बार भाजपा को समर्थन देंगे। वहीं, माकपा उम्मीदवार रामचंद्र मांडी का दावा है कि क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, लैम्प्स और कोल्ड स्टोरेज जैसे अधिकांश विकास कार्य वाममोर्चा सरकार के समय उपेन किस्कू के नेतृत्व में हुए थे।स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास के दावों के बावजूद इलाके में कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। रायपुर ग्रामीण अस्पताल को 100 बेड का दर्जा मिलने के बावजूद वहां पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं हैं। कृष्णपुर और गोयालडांगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहले चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधा मिलती थी, जबकि अब केवल एक समय ओपीडी चलती है। क्षेत्र में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की मांग भी लंबे समय से अधूरी है।इसके अलावा कंसाबती नदी पर सिमलिघाट और बामुंडीहा घाट पर पुल निर्माण की मांग वर्षों से लंबित है। किसानों के लिए इलाके में केवल एक कोल्ड स्टोरेज है, जिसकी क्षमता बढ़ाने और नए कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग उठ रही है। कई स्कूलों में आदिवासी छात्रावास बंद पड़े हैं, जबकि राज्य सड़कों की हालत खराब और पेयजल की समस्या भी लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

दांतन में देव का रोड शो, मानिक माइती के लिए मांगे वोट

पश्चिम मेदिनीपुर : वैशाख की तेज गर्मी और कड़ी धूप के बावजूद गुरुवार को दांतन विधानसभा क्षेत्र में मानिक माइती के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे देव को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। हर कोई अपने क्षेत्र के लोकप्रिय अभिनेता और सांसद देव की एक झलक पाने के लिए उत्सुक था। अभिनेता का लोगों ने जोरदार स्वागत कियामोहनपुर इलाके के गोमुंडा से बोड़ाई तक सत्तारूढ़ दल की ओर से एक बड़ा रोड शो निकाला गया। खुली गाड़ी में जैसे ही देव पहुंचे, शंखध्वनि और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आठ साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में भारी उत्साह देखा गया। भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे संभालने में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ी।रोड शो के दौरान माहौल तब और भी जोशीला हो गया, जब देव अचानक चलती गाड़ी के बोनट पर खड़े हो गए। फिल्मी अंदाज में हाथ हिलाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। अपने पसंदीदा

अभिनेता को इतने करीब देखकर समर्थक बेहद उत्साहित हो उठे।गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर ही देव ने लोगों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मानिक माइती के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों से 'जोड़ाफूल' चुनाव चिन्ह पर वोट देने का आग्रह किया, जिस पर लोगों ने तालियों के साथ समर्थन जताया।गौरतलब है कि इसी इलाके में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी रोड शो किया था, लेकिन उनका कार्यक्रम बीच में ही समाप्त हो गया था, जिससे कुछ समर्थकों में निराशा देखी गई थी। इसके विपरीत देव का पूरा रोड शो और लोगों से उनका सीधा संवाद स्थानीय लोगों को काफी प्रभावित करता नजर आया।रोड शो खत्म होने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। अपने पसंदीदा अभिनेता-सांसद के साथ फोटो खिंचवाने और उन्हें करीब से देखने की चाह लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी।

लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में लगी आग

सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी के अस्पताल मोड़ के पास स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यालय में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार रात सबसे पहले इमारत की छत पर बने एक कमरे से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके कुछ ही देर बाद आग ने विकराल रूप ले लिया।घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।कर्मचारियों ने बताया कि जिस कमरे में आग लगी, वह एक स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वहां एसी मशीन, बिजली के तार और अन्य उपकरण रखे हुए थे।फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है।

महिला शिक्षिका पर हेडमास्टर को जूते से पीटने का आरोप

कूचबिहार : जिले के तुफानगंज-2 ब्लॉक में ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) को लेकर विवाद के बीच बाघाजतिन शिशु शिक्षा केंद्र की प्रधान शिक्षिका आशालता पाल पर पश्चिम फेर्शाबाड़ी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक अभिजीत शिकदार को जूते से पीटने का आरोप लगा है।अभिभावकों के अनुसार, बाघाजतिन शिशु शिक्षा केंद्र में पढ़ाई का स्तर काफी खराब है, जिसके कारण सुचित्रा राय नाम की एक अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला पास के प्राथमिक विद्यालय में कराना चाहती थी। इसके लिए वे कई दिनों से टीसी मांग रही थी, लेकिन प्रधान शिक्षिका टालमटोल कर रही थी। गुरुवार को जब सुचित्रा राय ने रास्ते में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक अभिजीत शिकदार को यह बात बताई, तो वे इस मुद्दे पर बातचीत करने शिशु शिक्षा केंद्र पहुंचे।आरोप है कि वहां पहुंचते ही प्रधान शिक्षिका ने दरवाजा बंद कर उन्हें जूते से पीटना शुरू कर दिया।घायल प्रधान शिक्षक अभिजीत शिकदार का कहना है कि बिना किसी उकसावे के उनके साथ मारपीट की गई और इस दौरान वीडियो भी बनाया गया।वहीं, आरोपित शिक्षिका आशालता पाल ने आरोप लगाया कि प्रधान शिक्षक ने स्कूल में घुसकर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। हालांकि, स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों के एक बड़े वर्ग ने इस आरोप को खारिज कर दिया है।उनका कहना है कि स्कूल में मिड-डे मील के चावल की चोरी समेत कई अनियमितताएं हो रही है। छात्रों की संख्या कम होने के डर से टीसी देने में बाधा डाली जा रही है।घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों ने शिशु शिक्षा केंद्र में प्रदर्शन किया और शिक्षिका का घेराव किया। सूचना मिलने पर बक्शीरहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना को लेकर इलाके में भारी नाराजगी है। लोगों ने आरोपित शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

राज्य में उद्योग-धंधों की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ी : लखन घुरुई

आसनसोल : दुर्गापुर में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को एक अलग तरह का प्रचार देखने को मिला। दुर्गापुर के 12 नंबर वार्ड स्थित अमराई ग्राम में भाजपा उम्मीदवार लखन चंद्र घुरुई ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए खुद कड़ाही संभाली और आलू चप पकाते नजर आए। इस दौरान मौजूद लोगों की भीड़ ने इस अनोखे प्रचार को कैमरे में कैद किया।प्रचार के दौरान लखन चंद्र घुरुई ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में उद्योग-धंधों की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों को स्थायी रोजगार देने में विफल रही है और अब उन्हें आलू चप बेचने की सलाह दी जा रही है।उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोगों के पास आय का स्थायी साधन नहीं होगा, तो वे खरीदारी कैसे करेंगे। उनके मुताबिक, सिर्फ छोटे-मोटे व्यवसाय से राज्य की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती और यह मॉडल पूरी तरह से असफल साबित हुआ है।भाजपा उम्मीदवार ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। चुनावी माहौल में इस तरह के अलग अंदाज वाले प्रचार से राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज होती नजर आ रही है।

पूर्व रेलवे ने स्वच्छता क्रांति के साथ 173 वर्षों की रेल विरासत को नया रूप दिया

कोलकाता : 16 अप्रैल! 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक चली पहली भाप इंजन की गूंज आज भी इतिहास में प्रतिध्वनित होती है. इसी विरासत को सम्मान देते हुए, पूर्व रेलवे ने भारतीय रेल के 173 वें स्थापना दिवस को भविष्य के प्रति सक्रिय संकल्प के साथ मनाने का निर्णय लिया. पारंपरिक समारोहों से आगे बढ़ते हुए, ज़ोन ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को स्वच्छता के लिए एक ऊर्जावान अभियान में बदल दिया, जो एक महीने तक चलने वाले स्वच्छता जागरूकता अभियान का चरम बिंदु है. आज 16 अप्रैल की गतिविधियाँ विशेष रूप से कोच और ट्रैक की सफाई पर केंद्रित रहीं, इससे यह सिद्ध होता है कि गौरवशाली अतीत को सम्मान देने का सर्वोत्तम तरीका हर यात्री के लिए एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना है.

पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देऊस्कर ने कहा कि, जिस दिन भारत की धरती पर पहली बार पहिए चले थे, उस दिन का उत्सव मनाते हुए, हम एक स्वच्छ और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ अपनी विरासत का सम्मान करते हैं. यह केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारे यात्रियों के लिए एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य का वादा भी है. श्री मिलिंद देऊस्कर के नेतृत्व

में, यह कार्यक्रम आज पूर्व रेलवे नेटवर्क के हर कोने तक पहुँचा, जिसमें सभी प्रधान विभागाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, मंडल रेलवे प्रबंधकों, मंडल अधिकारियों और प्रत्येक कर्मचारी ने पूर्ण भागीदारी रही. महाप्रबंधक ने स्वच्छता के प्रति गहरी जागरूकता फैलाने के लिए हावड़ा स्टेशन का व्यक्तिगत दौरा किया और ट्रेनों में सवार यात्रियों से सीधे बातचीत की. इन बातचीत के दौरान, उन्होंने यात्रियों से व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया ली और उन्हें रेलवे ट्रैक पर कूड़ा न फेंकने और ट्रेन के डिब्बों के अंदर कचरा न डालने के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने यात्रियों को सलाह दी कि वे हमेशा उपलब्ध कूड़ेदानों का उपयोग करें या फिर ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ (ओबीएचएस) का इंतजार करें, जो सीटों से सीधे कूड़ा इकट्ठा करने के लिए नियुक्त हैं. इसके अलावा, उन्होंने समझाया कि यात्रियों को शौचालय का उपयोग करने के बाद हमेशा फ्लश का उपयोग करना चाहिए, ताकि वह अगले व्यक्ति के लिए उपयोग करने योग्य बना रहे, और बायो-टॉयलेट में कूड़ा न फेंकने की सख्त चेतावनी दी, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सिस्टम की खराबी से बचने के लिए वॉशरूम के विशिष्ट कूड़ेदान का ही उपयोग किया जाना चाहिए.

प्रत्यक्ष संपर्क की यह भावना पूरे क्षेत्र में देखने को मिली, क्योंकि अपर महाप्रबंधक, प्रधान विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और शाखा अधिकारियों ने जनता से बातचीत करने के लिए पूरे नेटवर्क का दौरा किया. वरिष्ठ अधिकारियों ने सियालदह, हावड़ा, मालदा और आसनसोल का दौरा किया, जिससे हजारों यात्रियों तक नागरिक जिम्मेदारी का संदेश पहुंचा.

इस प्रयास को पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की सक्रिय भागीदारी से बल मिला, जिन्होंने नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, रेलवे सुरक्षा बल और अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर स्टेशनों और डिब्बों पर अथक परिश्रम किया ताकि अभियान सफल हो सके.

इस उपलब्धि पर विचार व्यक्त करते हुए, पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी और पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य सचिव शिबराम माझी ने कहा कि स्वच्छ रेलवे बनाए रखना एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रतिदिन की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन पूरी तरह से स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वास्तविक सफलता यात्रियों के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं है. उन्होंने सभी यात्रियों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें. जब नागरिक और रेलवे मिलकर काम करते हैं, तो यह नेटवर्क केवल एक परिवहन प्रणाली नहीं रह जाता, बल्कि एक साझा घर बन जाता है.

बरहमपुर में रोड शो के दौरान बीमार पड़े मिथुन चक्रवर्ती

मुर्शिदाबाद : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल पूरी ताकत प्रचार-प्रसार में लगे हुए है। इसी क्रम में जिले के बरहमपुर में गुरुवार को रोड शो के दौरान बालिवुड अभिनेता और वरिष्ठ भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती बीमार पड़ गए। वे बरहमपुर से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत मित्रा के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। बरहमपुर में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे पक्ष में जनसैलाब है। हमारे उम्मीदवार की जीत होगी।सूत्रों के अनुसार, दिन का रोड शो बरहमपुर के गांधी कॉलोनी से शुरू हुआ जो पुराने कांदी बस स्टैंड से खगरा चौराहे तक जाना था। इसी दौरान अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने नतुन बाजार जॉय कालीबाड़ी के पास रोड शो खत्म कर दिया। भाजपा सूत्रों के अनुसार, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नतुन बाजार पहुंचने के बाद ही बीमार पड़ गए। अनुमान है कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण वह बीमार पड़े।हालांकि, अभिनेता मिथुन के बिना ही भाजपा उम्मीदवार सुब्रत मित्रा, जिलाध्यक्ष मलय महाजन और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने खगड़ा चौराहे तक जाकर रोड शो खत्म कर दिया।इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मलय महाजन ने कहा कि लोगों के इस जन आंदोलन में लोग इस बार जमीनी स्तर पर साबित हो चुकी भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।----

न्यूज कॉर्नर

जोरदार प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ सरकार

सिलीगुड़ी : पहले चरण के चुनाव में अब महज कुछ दिन बचे है, ऐसे में माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ सरकार ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने नक्सलबाड़ी के रथखोला और टुकुरिया मोड़ इलाकों में जनसंपर्क शुरू किया।प्रचार के दौरान वह आम लोगों के बीच पहुंचे और दुकानों में जाकर समर्थन मांगा। इस दौरान वह तृणमूल के एक बूथ पर भी गए और वहां मौजूद पंचायत सदस्य से बातचीत की।अमिताभ सरकार ने कहा कि वह क्षेत्र के सभी समाज और वर्ग के लोगों के पास जाकर वोट की अपील कर रहे है। पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान शुरू हो चुका है और इस पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी उम्मीदवारी से घबराकर भाजपा नरेंद्र मोदी और तृणमूल ममता बनर्जी को प्रचार में उतार रही है।

मतदाताओं में भरोसा बढ़ाने मैदान में उतरे डीएम और एसपी

सिलीगुड़ी : मतदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक बूथ-बूथ पर पहुंच रहे हैं। आगामी 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने वाला है। इसी बीच, आठ अप्रैल को नक्सलबाड़ी में तृणमूल और बीजेपी के बीच झड़प की घटना हुई थी।इसी को देखते हुए नक्सलबाड़ी के रायपाड़ा इलाके में लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए बुधवार रात दार्जिलिंग के जिलाधिकारी हरिशंकर पनिकर और जिला पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा झारखंडिया पहुंचे। उन्होंने नक्सलबाड़ी के रायपाड़ा और नंद प्रसाद बालिका विद्यालय के बूथों का निरीक्षण किया और आम लोगों को आश्वस्त किया।इस दौरान केंद्रीय बलों के साथ इलाके में गश्त भी की गई। जिलाधिकारी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत हो, तो वह 1905 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

दामोदर नदी पर स्थायी ब्रीज का निर्माण बना चुनावी मुद्दा

आसनसोल : दामोदर नदी पर स्थायी ब्रिज निर्माण का मुद्दापश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल का प्रमुख चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है। पिछले सात वर्षों से दामोदर सेतु बंधन कमेटी इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। कमेटी ने बांकुड़ा और पश्चिम बर्दवान के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कई बार आवेदन किया, लेकिन अब तक पुल निर्माण का सपना साकार नहीं हो सका। हालांकि अब यह आंदोलन आम जनता की भागीदारी से एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले चुका है।बुधवार की रात दामोदर बिहारी नाथ सेतु बंधन कमेटी के फेसबुक पेज पर बिहारी नाथ सेतु का एक फोटो साझा किया गया है। जिस पर लोगों ने अलग-अलग कॉमेंट के माध्यम से खुशी जाहिर की।चुनावी माहौल में इस मुद्दे की अहमियत और भी बढ़ गई है। सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने घोषणा पत्र में बामनटोड़ा ग्राम पंचायत के फेरी घाट से नेहरू पार्क तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे स्थायी ब्रिज के निर्माण का वादा किया है। वहीं आसनसोल दक्षिण सीट पर उम्मीदवारों ने इसे प्राथमिक मुद्दा बनाते हुए बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम बर्दवान को जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर सेतु निर्माण की बात कही है।आसनसोल उत्तर के घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को पहला स्थान दिया गया है, जिसमें क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बांकुड़ा और आसपास के इलाकों को सीधे जोड़ने हेतु पुल निर्माण को जरूरी बताया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने राज्य घोषणा पत्र में दामोदर नदी पर पुल निर्माण का वादा किया है।भाजपा की ओर से अग्निमित्रा पॉल ने इस मुद्दे को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया और इसे चुनावी एजेंडा बनाया। उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जहाजरानी विभाग के माध्यम से ब्रिज निर्माण के लिए सर्वे भी करवाया, लेकिन नदी की भौगोलिक स्थिति के कारण फेरी सेवा शुरू करना संभव नहीं हो सका।दूसरी ओर तृणमूल नेता और राज्य के मंत्री मलय घटक ने अगस्त 2021 में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स (राइस) को जियोलॉजिकल सर्वे का जिम्मा सौंपा था। इस सर्वे पर करीब 75 लाख रुपये खर्च हुए और एक महीने के भीतर रिपोर्ट भी जमा कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।राज्य सरकार की ओर से वित्तीय अड़चन सबसे बड़ी बाधा बनी रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर के प्रशासनिक बैठक के दौरान दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने का से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि यह राज्य सरकार के अधीन नहीं है दामोदर नदी पर ब्रिज केंद्र सरकार को बनाना होगा। वर्तमान समय में इस पुल के निर्माण में लगभग 350 करोड़ रुपये का खर्च का आकलन किया जा रहा है।दामोदर सेतु बंधन कमेटी के महासचिव चंदन मिश्रा के अनुसार, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद आंदोलन को नई दिशा मिली और यह एक बड़े जनआंदोलन में तब्दील हो गया। अब क्षेत्र की जनता की नजरें 2026 के चुनाव पर टिकी हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्षों से उठ रही यह मांग आखिरकार जमीन पर उतरती है या फिर एक बार फिर चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाती है।दामोदर नदी पर बने स्थायी बांस का सेतु पर पश्चिम बर्दवान, बांकुड़ा और पुरुलिया के लगभग 300 गांवों की जिंदगी टिकी हुई है। आसनसोल और बर्नपुर के बीच रिवरसाइड घाट पर बना यह स्थायी पुल इन इलाकों के लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही का मुख्य साधन है।

सख्ती: ईवीएम में 'इत्र' और 'च्यूइंगम' से छेड़छाड़ पर होगा री-पोल

कोलकाता: बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी बूथ पर वोटरों को डराने या वेबकैम से छेड़छाड़ करने जैसी शिकायतें मिलती हैं, तो वहां दोबारा मतदान (री-पोल) कराया जाएगा. अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि कुछ लोग वोटरों को धमकाते हैं कि ईवीएम के बटन पर इत्र लगाया गया है और बाहर निकलते ही गंध से पता चल जाएगा कि किसे वोट दिया गया. इसके अलावा, बूथ पर फर्जी मतदान कराने के लिए वेबकैम पर च्यूइंगम चिपकाकर उसे बंद करने जैसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं. अब ऐसी किसी भी गड़बड़ी पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा. चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मतदान के दौरान वेबकास्टिंग किसी भी हाल में बाधित न हो. अगर किसी बूथ पर लगातार आधे घंटे तक वेबकास्टिंग बंद रहती है, तो वहां भी री-पोल कराया जा सकता है. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुख्य सचिव दुष्मंत नारियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष, पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें फैसला लिया गया कि मतदान से पहले और बाद में किसी भी इलाके में लोडशेडिंग न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा. अगर खराब मौसम या तकनीकी खराबी से बिजली चली जाती है, तो तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं. कई इलाकों में हर बूथ पर जनरेटर रखने की योजना है, साथ ही सेक्टर आफिस में भी अतिरिक्त जनरेटर उपलब्ध रहेंगे. राज्य में नेटवर्क की समस्या वाले 642 इलाकों को 'शैडो जोन' के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें दार्जिलिंग और कालिंपोंग जैसे पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं. यहां इंटरनेट सेवाएं बेहतर रखने के लिए टेलीकाम कंपनियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि वेबकास्टिंग एक पल के लिए भी बंद न हो. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मतदान से सात दिन पहले बूथों पर कैमरे लगाए जाएंगे और दो दिन पहले से वेबकास्टिंग शुरू कर दी जाएगी. पहले चरण के मतदान में 152 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2,404 कंपनियां केंद्रीय बल की तैनाती की जा रही है. हर बूथ पर केंद्रीय सशस्त्र बल और एक लाठीधारी पुलिसकर्मी की मौजूदगी अनिवार्य की गई है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके.

बीएसएफ कैंप हिंगलगंज में लगी भीषण आग, एक जवान शहीद

ईंधन भरते समय आग लगने की आशंका

कोलकाता: बंगाल के उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज इलाके में बीएसएफ के एक कैंप में आग लगने से एक जवान की मौत हो गई. मृतक की पहचान एएसआई जगी राम के रूप में हुई है. वह सूत्रों के अनुसार, यह हादसा गुरुवार सुबह हिंगलगंज के बांकरा स्थित बीएसएफ की 77वीं बटालियन के कैंप में हुआ. बताया जा रहा है कि ज्योति राम सिंह कैंप के उस कमरे में गए थे, जहां ईंधन (फ्यूल) का भंडारण किया जाता है. इसी दौरान स्पीडबोट में तेल भरते समय अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैल गई कि वह बाहर निकलने का मौका नहीं पा सके और कमरे के अंदर ही फंस गए. गंभीर रूप से झुलसने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि किसी के लिए अंदर जाना संभव नहीं हो सका. सूचना मिलते ही हासनाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. बीएसएफ जवानों, पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके. बाद में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इसके बाद ज्योति राम सिंह को बाहर निकालकर बशिरहाट अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हिंगलगंज थाने के प्रभारी संदीप दास ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बीएसएफ कैंप में आग लगने की घटना में एक एएसआई की मौत हुई है. प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा शार्ट सर्किट या ईंधन से जुड़ी लापरवाही के कारण हुआ हो सकता है. हालांकि, आग लगने के सही कारणों की जांच जारी है.

बंगाल चुनाव में 'रसोईघर' और कलछी की खनक

जनता के दिल तक पहुंचने के लिए इमेज बिल्डिंग का नया हथियार

कोलकाता: बंगाल की चुनावी राजनीति अब केवल दीवार लेखन, रैलियों और जोशीले भाषणों तक सीमित नहीं रह गई है. इस बार के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक तर्कों से ज्यादा शोर कढ़ाई में कलछी (हता-खुन्ती) चलाने का सुनाई दे रहा है. कोई उम्मीदवार सड़क किनारे ढाबे पर रोटियां बेलता नजर आ रहा है, तो कोई मछली तलने में व्यस्त है. बंगाल में अब 'किचन पालिटिक्स' (रसोईघर की राजनीति) का दौर पूरी तरह से हिट हो चुका है. जनसंपर्क की यह अनूठी शैली कभी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का 'सिग्नेचर स्टाइल' मानी जाती थी. पहाड़ पर मोमो बनाना हो या तेल में डूबी गरम जलेबियां छानना, आम लोगों के बीच घुलमिल जाने की इस कला में वह माहिर रही हैं. लेकिन इस चुनाव में सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक, हर कोई इसी राह पर है. कामरहाटी के उम्मीदवार मदन मित्रा कभी चाय की दुकान पर चाय बनाते दिखते हैं, तो कभी सड़क किनारे खाना पकाते. आसनसोल दक्षिण में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल को रोटियां बेलते देखा गया. डीवाईएफआइ नेता मीनाक्षी मुखर्जी को नंदीग्राम में ग्रामीणों के साथ सब्जियां काटते देखा गया, जबकि कसबा में शतरूप घोष आम लोगों के चूल्हे के पास हाथ बंटाते नजर आए. आरामबाग की उम्मीदवार मिताली बाग तो एक कदम आगे बढ़कर खेत में धान की रोपाई करती और चूल्हे के पास बैठकर महिलाओं से बतियाती दिखीं. वहीं, भाजपा के शरद्वत मुखर्जी हाथ में मछली लेकर प्रचार करते दिखे, जिसे खान-पान की राजनीति का जवाब माना जा रहा है. नारायणगढ़ की प्रतिभा रानी माइती साइकिल चलाकर प्रचार कर रही हैं और ग्रामीणों के भोजन बनाने में मदद कर रही हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मतदाताओं के करीब पहुंचने की एक प्रभावी 'इमेज बिल्डिंग' रणनीति है. एसी कमरों से बाहर निकलकर खुद को 'माटी का मानुष' (धरती से जुड़ा इंसान) दिखाना और इंटरनेट मीडिया पर इन तस्वीरों को वायरल कराके भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है. सवाल यह है कि चुनाव के बाद भी क्या ये प्रत्याशी रसोई की सुध लेंगे, या यह प्रेम केवल वोट की खातिर है?

अभिषेक बनर्जी ने शाह को मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहने की दी चुनौती

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहने की बृहस्पतिवार को चुनौती दी. पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर में एक चुनावी रैली में बनर्जी ने कहा, अगर आपमें हिम्मत है, तो मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहें, तब हम देखेंगे. उन्होंने ममता बनर्जी के चौथी बार मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में लौटने का विश्वास व्यक्त किया. राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे. मतगणना चार मई को होगी. भाजपा नेताओं से धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, हमें धमकियां मिल रही हैं. गृह मंत्री कह रहे हैं कि तृणमूल कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर न निकलें वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहां आकर बंगाल के लोगों को धमकाए. चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल में आरोप-प्रत्यारोप बढ़ने के बीच, बनर्जी ने संभावित राजनीतिक प्रतिशोध का संकेत दिया. उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैंने एक सूची तैयार की है- ब्लॉक दर ब्लॉक, पंचायत दर पंचायत. सूद सहित हिसाब चुकता किया जाएगा. भाजपा ने अतीत में दावा किया था कि तृणमूल शासन के दौरान उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और उन्हें डराया-धमकाया गया. बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. तृणमूल महासचिव ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आयकर विभाग, निर्वाचन आयोग - किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा. आप जितना हमें बदनाम करेंगे, हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे. इस मुकाबले को दिल्ली की सत्ता और बंगाल की जनता के बीच की लड़ाई बताते हुए उन्होंने कहा, एक तरफ दिल्ली के शक्तिशाली नेता, संस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ बंगाल के 10 करोड़ लोग और चप्पल पहने एक महिला हैं. बनर्जी ने भाजपा पर बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर उनका अपमान करने और उनकी खान-पान की पसंद को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया तथा मतदाताओं से वोट के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देने का आग्रह किया.

'बंगाल में भाजपा के लिए असली काम कर रहा है चुनाव आयोग'

कोलकाता: सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बंगाल में भाजपा के लिए असली काम कर रहा है. उन्होंने लिखा कि यदि कोई यह मानता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ बंगाल में भाजपा के ट्रंप कार्ड हैं, तो यह गलत है. उनके अनुसार, पर्दे के पीछे से वास्तविक भूमिका चुनाव आयोग निभा रहा है और भाजपा के निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा आदेश देती है और चुनाव आयोग उसे मानने के लिए बाध्य रहता है. कहा कि चुनावी माहौल में उनके परिवार और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार ने बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की है. करीब 2550 कंपनियों की तैनाती को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है. अभिषेक बनर्जी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन बलों की अधिक जरूरत अन्य राज्यों में है, लेकिन उन्हें बंगाल में लगाया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद स्थिति बदल जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आज उनके कार्यकर्ताओं को रोकने या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे परिणाम के बाद राज्य में नहीं दिखेंगे.

बंगाल में करोड़पति उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर तृणमूल

कोलकाता: बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसने चुनावी राजनीति में धन के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया है. चुनावी पारदर्शिता पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के विश्लेषण के मुताबिक, कई उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में तृणमूल सबसे अधिक करोड़पति उम्मीदवारों वाली पार्टी बनकर उभरी है. पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को निर्धारित है, जिसमें 152 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,478 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए 106 उम्मीदवारों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है, जिससे करोड़पति प्रतिनिधित्व के मामले में यह पार्टी सबसे आगे है. टीएमसी ने इस चरण में 148 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से लगभग 72 प्रतिशत उम्मीदवार चुनाव आयोग को हलफनामे में प्रस्तुत चल और अचल संपत्तियों के आधार पर करोड़पति श्रेणी में आते हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 152 उम्मीदवारों में से 71 ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है. कांग्रेस के 50 उम्मीदवार ऐसे हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के पहले चरण में 24 करोड़पति उम्मीदवार हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस चरण के तीनों सबसे धनी उम्मीदवार टीएमसी से हैं. इनमें से जंगीपुर से जाकिर हुसैन ने 133 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है, जिससे वे इस चरण के सबसे धनी उम्मीदवार बन गए हैं. बरजोरा से गौतम मिश्रा ने 105 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है और उन पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का सबसे अधिक घोषित कर्ज भी है. दुर्गापुर पश्चिम से टीएमसी के एक अन्य उम्मीदवार, कबी दत्ता ने 72 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है, और ये तीनों उम्मीदवार मुख्य रूप से व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए हैं.

संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सीसीटीवी कैमरे, सामान्य केंद्रों पर दो-दो कैमरे लगाए जाएंगे

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी तरह निगरानी में रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सीसीटीवी कैमरे और सामान्य मतदान केंद्रों पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाए जाने वाले तीन सीसीटीवी कैमरों में से दो कैमरे मतदान केंद्र के अंदर और एक कैमरा बाहर लगाया जाएगा. वहीं सामान्य मतदान केंद्रों में एक कैमरा अंदर और एक कैमरा बाहर लगाया जाएगा. ये सभी कैमरे जिला नियंत्रण कक्षों से जोड़े जाएंगे, जो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थित होंगे.

कूचबिहार में केंद्रीय बल के 14 जवान बीमार, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले यहां तैनात केंद्रीय बल के 24 जवान अचानक बीमार पड़ गए, जिसके बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है. मामला कूचबिहार जिले के तुफानगंज के तल्लीगुड़ी हाई स्कूल की है, जहां ये सभी जवान ठहरे हुए थे. इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. सीईओ कार्यालय सूत्रों के मुताबिक, बॉक्सिरहाट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सालबारी-2 के तालीगुड़ी हाई स्कूल में तैनात 'एड हॉक-601, सी कंपनी के 14 जवानों ने पेट दर्द और बदन दर्द की शिकायत की. उन्हें तूफानगंज उपजिला अस्पताल भेजा गया. इलाज के बाद 10 को छुट्टी दे दी गई और चार को अस्पताल में निगरानी में रखा गया है. 'एड हॉक 601, आईटीबीपी' के मेडिकल ऑफिसर मरीजों के साथ थे. बाद में, कूचबिहार के तूफानगंज महकमा अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बात की. सूत्रों के अनुसार, जवान सोमवार को असम के नागांव से कूचबिहार पहुंचे थे. माना जा रहा है कि लंबी सड़क यात्रा के दौरान डिहाइड्रेशन और ओवरहेड वॉटर टैंक के खराब पानी में पकाए गए खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई. फिलहाल, चिकित्सक उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामले में वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसे तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, जवान उसी स्कूल परिसर में स्वयं खाना बनाकर खा रहे थे. बुधवार सुबह से कुछ जवानों को पेट दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद एक-एक कर कुल 14 जवान बीमार पड़ गए. कई जवानों को गंभीर पेट संबंधी समस्या होने पर तत्काल स्कूल से हटाकर तुफानगंज महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों का अनुमान है कि यह मामला खाद्य विषाक्तता का हो सकता है. हालांकि, इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी. आगामी 23 अप्रैल को राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है. इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं. आयोग के निर्देशानुसार 18 अप्रैल से बलों की तैनाती शुरू कर 20 अप्रैल तक इसे पूरा किया जाना है.

तृणमूल ने हुमायूं कबीर पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, आयोग से की कार्रवाई की मांग

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना चुके हुमायूं कबीर ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेजे गए ई-मेल में हुमायूं कबीर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. शिकायत के साथ एक प्रेसवार्ता का वीडियो भी संलग्न किया गया है, जिसमें कबीर कथित रूप से ऐसे बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं. इन टिप्पणियों में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है.

स्मृति ईरानी व शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता स्मृति ईरानी, शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि 15 अप्रैल को भाजपा नेताओं ने 'मातृशक्ति भरोसा कार्ड' नामक एक नई योजना की घोषणा की. इसके तहत महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में देने का वादा किया जा रहा है. साथ ही विभिन्न स्थानों पर इस योजना के फॉर्म भी बांटे जा रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घोषणाएं और फॉर्म वितरण चुनाव आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन हैं. पार्टी के अनुसार, महिलाओं को इस योजना के तहत प्रलोभन देकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इसके बदले नकद या प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के जरिए आर्थिक लाभ देने की बात कही जा रही है. पार्टी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का समय, तरीका और स्वरूप यह दर्शाता है कि यह कोई सामान्य या परोपकारी पहल नहीं है, बल्कि चुनाव के नजदीक सुनियोजित तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है. उल्लेखनीय है कि, बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोलकाता में मौजूद थीं, जहां उन्होंने महिलाओं के बीच 'मातृशक्ति भरोसा कार्ड' का वितरण भी किया. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना के खिलाफ हैं और इससे मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद प्रभावित होती है, साथ ही चुनावी मैदान में बराबरी का स्तर भी बिगड़ता है. पार्टी ने इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में बताया है. साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2), 173 और 174 के तहत दंडनीय अपराध भी करार दिया है.

बिना बाउंड्री वाले मतदान केंद्रों पर बांस की घेराबंदी का निर्देश

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने ऐसे मतदान केंद्रों के चारों ओर अस्थायी बांस की घेराबंदी करने को कहा है, जहां पक्की चारदीवारी मौजूद नहीं है, ताकि अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकी जा सके. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने कई ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की है जो स्कूल भवनों में स्थित हैं और जिनके चारों ओर कोई समुचित बाउंड्री वॉल नहीं है. इससे वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की निगरानी से बचकर बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है. सूत्र ने बताया कि कुछ मतदान केंद्र दूरदराज के वन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां चारों ओर घने जंगल या झाड़ियां हैं. ऐसे इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम अधिक है.

मोथाबारी मामला: आरोपी मोफक्करुल की भूमिका पर विस्तृत बयान प्रस्तुत

एनआईए ने कहा- आरोपी की भूमिका रहस्यमय, पूछताछ जरूरी

कोलकाता : मालदा के मोथाबारी में न्यायिक अधिकारियों को घेरकर विरोध प्रदर्शन करने की घटना को लेकर अदालत में फिर से हंगामा मच गया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य आरोपी मोफक्करुल के वकील ने आरोपी की भूमिका पर विस्तृत बयान प्रस्तुत किया. उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया कि उनके मुवक्किल को पूरी घटना के लिए अनुचित रूप से दोषी ठहराया जा रहा है और यह असली दोषियों को फंसाने का प्रयास है. मोफक्करुल के वकील ने कोलकाता की विशेष एनआईए अदालत को बताया कि घटना के बाद पुलिस जांच शुरू होने के महज तीन दिन बाद ही उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपपत्र में कहा गया है कि उस रात करीब 12:15 बजे 700 से 800 लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हुई, जिनमें से कुछ लोग आगे-आगे चल रहे थे. हालांकि कुल पांच नामों का जिक्र है, लेकिन मोफक्करुल का नाम सूची के अंत में रखा गया है - जिस पर उनके वकीलों ने पहले ही सवाल उठाए हैं. वकील के अनुसार, मोफक्करुल उस रात करीब 9:30 बजे कालियाचक पहुंचे और विरोध प्रदर्शनों के कारण वहीं फंस गए. बाद में, वे रात 10:30 बजे सुजापुर पहुंचे. उस समय, प्रशासन ने उनसे प्रदर्शनकारियों को शांत करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद करने का अनुरोध किया. उनके वकील का दावा है कि उन्होंने उस अनुरोध पर एक संक्षिप्त भाषण दिया. वकील ने अदालत में आगे कहा, मेरे मुवक्किल के महज 10 मिनट के भाषण में कोई भड़काऊ टिप्पणी नहीं थी. बल्कि, प्रशासन के अनुरोध पर उन्होंने माइक पर घोषणा की और भीड़ को तितर-बितर करने में मदद की. यह घोषणा उस समय पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में की गई थी. उन्होंने दावा किया कि मोफक्करुल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बात की और उस भाषण के परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे तितर-बितर होने लगे. हालांकि, इस तर्क को जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया है. एनआईए के वकील ने अदालत को बताया कि मोफक्करुल को हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था और इस घटना में उसकी भूमिका रहस्यमय है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जांच के लिए उससे आगे पूछताछ करना आवश्यक है. एनआईए ने कहा कि घटना में उसकी संलिप्तता की गहराई जानने के लिए विस्तृत पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण है. मोथाबारी मामले में न्यायिक अधिकारियों को धमकाने के गंभीर आरोपों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में पहले से ही काफी हलचल मची हुई है. एक ओर, आरोपी के वकील का दावा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को निशाना बनाया गया है. दूसरी ओर, जांच एजेंसी गहन जांच पर जोर दे रही है. इस स्थिति में, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब अदालत की आगे की टिप्पणियां और निर्देश बेहद महत्वपूर्ण हैं. सभी की निगाहें मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

आपकी वेदना, हमारी संवेदना

युवा शक्ति समाचार पत्र उठावना का विज्ञापन मात्र 1500 रुपये में प्रकाशित करता है

(साइज 12x8)

सम्पर्क :
मो. : 9831572125, 9831494084
www.yuvashakti.news.com
email: yuvashakti@hotmail.com

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं.: 222-एस/1/डब्ल्यू- II, दिनांक 13.04.2026; वरिष्ठ मंडल अभियंता/I, पूर्व रेलवे, सियालदह, रिमोट कंट्रोल बिल्डिंग, डीआरएम बिल्डिंग, कमरा सं. 44, कैजर स्ट्रीट, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए नीचे उल्लेखित ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं: क्रमांक 1. निविदा सं.: टीएन-04-26-27; कार्य का नाम: स्पैन सं. 5, 6 एवं 7 के लिए पुल सं. 13 सीसीआर की मेटलाइजिंग तथा सैंड ब्लास्टिंग का प्रावधान। निविदा मूल्य: रु. 4,33,37,408.50; ईएमडी: रु. 8,66,800; क्रमांक 2. निविदा सं.: टीएन-05-26-27; कार्य का नाम: वरिष्ठ मंडल अभियंता/1/सियालदह के अधिकार क्षेत्र के अधीन टीबीआर-17.473 किमी, टीबीआर प्वाइंट एवं क्रॉसिंग-31 सेट, टीएसआरपी-4.688 टीकेएम, टीटीआर-50 सेट, टीएफआर-19.218 किमी, टीबीआरपी-4.934 किमी तथा अन्य आनुषंगिक कार्य। निविदा मूल्य: रु. 4,73,09,061.86; ईएमडी: रु. 9,46,200; कार्य समापन अवधि: 18 (अठारह) महीने (दोनों के लिए)। निविदा बंद होने की तारीख एवं समय: 08.05.2026 को अपराह्न 03.00 बजे (दोनों के लिए)। निविदा खुलने की तारीख एवं समय: 08.05.2026 को अपराह्न 03.30 बजे (दोनों के लिए)। निविदा दस्तावेज एवं अन्य विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा के लिए बोलियां उपरोक्त वेबसाइट पर ई-निविदा प्रणाली के जरिए जमा की जानी चाहिए। मैनुअल प्रस्ताव तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे।

(SDAH-05/2026-27)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

संपादकीय

कामयाब होने के लिए स्वयं पर भरोसा होना चाहिए

कोलकाता | शुक्रवार | 17 अप्रैल, 2026

बढ़ेगा गरीबी का दायरा

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की पश्चिम एशिया युद्ध से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करने वाली रिपोर्ट के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं. रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी में ईरान–अमेरिकी युद्ध से उपजी परिस्थितियों के चलते भारत में और 25 लाख लोग गरीबी की दलदल में फंस सकते हैं. साथ ही मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका पैदा हो गई है. रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. रिपोर्ट बताती है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से लोगों की घरेलू क्रयशक्ति घट रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है. वहीं विकास कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है. इसके अलावा आजीविका के अवसर कम हो रहे हैं. इस संकट में जहां पूरे विश्व में 88 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने की आशंका है, वहीं भारत में यह अनुमानित संख्या 25 लाख है. रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एशिया–प्रशांत में तकरीबन 299 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है. हालांकि, भारत की बड़ी आबादी के सामने बढ़ने वाली गरीबों की संख्या छोटी है, लेकिन इससे भारत में गरीबी की दर बढ़ सकती है, जिसके 35.40 करोड़ होने की आशंका है. दरअसल, आज भी भारत करीब 90 फीसदी तेल जरूरतों के लिए आयात पर आश्रित है. हम कच्चे तेल का 40 फीसदी से अधिक और रसोई गैस का 90 फीसदी आयात पश्चिम एशिया से करते हैं. साथ ही हम अपने उर्वरकों का 40 फीसदी हिस्सा युद्धग्रस्त पश्चिमी एशिया से आयात करते हैं. एलएनजी की कीमतों में वृद्धि से कोयला आधारित बिजली पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी. वहीं दूसरी ओर व्यापार व आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई है. आशंका है कि संघर्ष से रेमिटेंस में भी कमी आएगी. निस्संदेह, मालभाड़ा शुल्क, युद्ध जोखिम बीमा, मार्ग परिवर्तन और देरी की वजह से आयातित तेल आदि की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे आयात मूल्य में वृद्धि व निर्यात का नुकसान बढ़ा है. असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है. वहीं खाद की आपूर्ति में बाधा का असर खरीफ की फसल पर पड़ने की आशंका है. इस सब के चलते बढ़े दामों का प्रभाव आम आदमी की जेब पर हो रहा है, जिसका रोजगार और आय के मामले में असर बड़ी आबादी पर नजर आ रहा है. हाल ही में नोएडा और मानेसर में श्रमिक असंतोष को इसी परिणति के रूप में महसूस किया जा सकता है. दरअसल, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है. आर्थिक परेशानियों के चलते आम आदमी अब अपने जरूरी खर्चों में कटौती कर रहा है. वजह है उसकी आय के साधन सीमित होना. वहीं निम्न आय वर्ग के लोगों में इससे भरण–पोषण का संकट पैदा हो रहा है. श्रमिक असंतोष के बीच आक्रोश उभरा कि महंगाई के अनुपात में उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, फलत: जीवनयापन कठिन होता जा रहा है. सरकार की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया कि मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4 हो गई है, जिसकी वजह पश्चिमी एशिया से उपजा संकट बताया जा रहा है. सवाल यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास सिरे क्यों नहीं चढ़ रहे हैं. यदि कदम प्रभावकारी हैं तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है. वास्तव में खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को महंगाई का मुख्य कारण बताया जा रहा है. यद्यपि सरकार की दलील है कि खुदरा महंगाई दर केंद्रीय बैंक की रेड लाइन चार फीसदी से नीचे है. लेकिन वास्तव में स्थिर आय के चलते महंगाई अधिक महसूस की जा रही है. लेकिन लोगों की चिंता यह है कि यदि पश्चिम एशिया संकट का शीघ्र समाधान नहीं निकलता है तो महंगाई की मार असहनीय हो सकती है. यदि समय रहते सरकार की तरफ से ठोस प्रयास किए जाते हैं तो महंगाई पर अंकुश लगाना संभव हो पायेगा.

पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी बनता डिजिटल प्रदूषण

– डॉ. सुधीर कुमार

जब हम 'प्रदूषण' शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जहरीला धुआं उगलती चिमनियां, प्लास्टिक से पटी नदियां या सड़कों पर लगा कचरे का ढेर उभरता है. ये प्रदूषण के वे रूप हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. लेकिन इक्कीसवीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ एक ऐसा अदृश्य जहर हमारे वातावरण और जीवन में घुल चुका है, जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन वह धीरे-धीरे हमारे पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है. इसे हम 'डिजिटल प्रदूषण' कहते हैं. भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी चरम पर है और 'डिजिटल इंडिया' का सपना साकार हो रहा है, इस अदृश्य खतरे पर कानून, नीति और जनजागरूकता के नजरिये से चर्चा करना अनिवार्य हो गया है. लोग डिजिटल प्रदूषण को केवल 'ई-वेस्ट' यानी पुराने मोबाइल, टूटे लैपटॉप या खराब चार्जर तक सीमित मान लेते हैं. बेशक, ई-कचरा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'अभौतिक' है. इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशत: जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है. जब हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो हजारों मील दूर स्थित विशाल डेटा सेंटर्स सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है. अत:, डिजिटल गतिविधियों का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है. डिजिटल प्रदूषण के दो सबसे घातक पहलू 'डार्क डेटा' और 'डिजिटल फुटप्रिंट' हैं. 'डार्क डेटा' वह अनुपयोगी डेटा है जो कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा केवल स्टोर किया जाता है, जिसका दुनिया भर के कॉर्पोरेट डेटा में हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है. यह डेटा केंद्रों में व्यर्थ ऊर्जा की खपत करता है. वहीं, हमारा 'डिजिटल फुटप्रिंट' भी उतना ही खतरनाक है; एक स्पैम ईमेल अपने पूरे जीवनचक्र में लगभग 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का जिम्मेदार है. यदि हम दुनियाभर में प्रतिदिन भेजे जाने वाले अरबों स्पैम और अनावश्यक ईमेल की गणना करें, तो यह प्रदूषण का स्तर वैश्विक विमानन उद्योग द्वारा फैलाए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाता है. यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एक छोटी-सी डिजिटल लापरवाही धरती के तापमान को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है. भारत में 'डिजिटल प्रदूषण' को सीधे तौर पर परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट या एकल कानून मौजूद नहीं है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और समय-समय पर संशोधित ई-कचरा प्रबंधन नियम (2016/2022) इसके केवल भौतिक हिस्से (हार्डवेयर कचरे) को कवर करते हैं. असली चुनौती डेटा केंद्रों से होने वाले ऊर्जा उत्सर्जन और 'डिजिटल हाइजीन' की है, जिसके लिए वर्तमान में स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों की कमी खलती है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है. यद्यपि ये मामले पारंपरिक औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित थे, लेकिन इनमें स्थापित 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा' और 'एहतियाती सिद्धांत' का दर्शन डिजिटल दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए. जो कंपनियां विशाल डेटा सेंटर चलाती हैं और करोड़ों भारतीयों का डेटा प्रोसेस करती हैं, वे डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं. 'भारत सरकार द्वारा 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल का शुभारंभ एक क्रांतिकारी पहल है. कानूनी और नीतिगत रूप से यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है कि वे अपने गैजेट्स को कंपनियों के एकाधिकार से बाहर निकलकर ठीक करा सकें. यह पहल न केवल कंपनियों की 'प्लांड ऑब्सोलेसेंस' (गैजेट्स को जानबूझकर ऐसा बनाना कि वे जल्दी खराब हो जाएं) की नीति पर लगाम लगाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में भी मील का पत्थर साबित होगी. जब कोई उपकरण लंबा चलेगा, तो उसके निर्माण में लगने वाली ऊर्जा और उससे बनने वाले कचरे से होने वाला प्रदूषण में स्वत: कमी आएगी. 'केवल कानून और अदालती आदेश डिजिटल प्रदूषण का पूर्ण समाधान नहीं हैं; इसके लिए 'डिजिटल स्वच्छता' को जीवनशैली बनाना अनिवार्य है. शुरुआत इनबॉक्स की सफाई, अनावश्यक न्यूजलेटर्स को अनसब्सक्राइब करने और क्लाउड स्टोरेज से धुंधली तस्वीरों व पुराने बैकअप को हटाकर की जा सकती है. इसके साथ ही, वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान 'अति-उच्च परिभाषा' के बजाय सामान्य स्पष्टता का चुनाव करना डेटा केंद्रों पर दबाव और बिजली की खपत को कम करता है. यह 'डिजिटल क्लीन-अप' न केवल डेटा व्यवस्थित करता है, बल्कि ऊर्जा की बचत कर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अब सरकार को 'ग्रीन डेटा कानूनों' के माध्यम से टेक कंपनियों को अक्षय ऊर्जा (सौर, पवन) अपनाने और डेटा केंद्रों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए जवाबदेह बनाना होगा. हमें समझना होगा कि डेटा भले ही आभासी हो, पर उसे चलाने वाली ऊर्जा भौतिक है, जो धरती को प्रभावित करती है. आज समय की मांग है कि हम 'डिजिटल डिटॉक्स' के साथ-साथ 'डिजिटल क्लीन-अप' को अपनाएं. ***(लेखक कुरुक्षेत्र विवि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं)***

इस्लामाबाद वार्ता में प्रवाह के सिद्धांत की अनदेखी

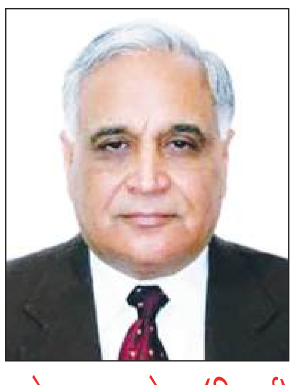

– ले.ज. एसएस मेहता (रिटायर्ड)

पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से होर्मुज गतिरोध की बात करें तो दुनिया के संकरे द्वारों में निरंतर आवाजाही ही स्थिरता प्रदान कर सकती है. आपूर्ति शृंखलाएं, वित्तीय प्रणालियां और डिजिटल नेटवर्क वैश्विक प्रणाली की जीवन रेखाएं हैं. राजनीति इस प्रवाह की संरक्षक' बननी चाहिये. लेकिन इस्लामाबाद वार्ता में यह मिसाल कायम नहीं हो सकी.

आधुनिक दुनिया बात तो करती है शांति की, लेकिन व्यवहार करती है व्यवधान की मशीनरी के ज़रिए. युद्ध अब केवल सीमाओं या खंदकों तक सीमित नहीं; आपूर्ति शृंखलाएं बाधित होती हैं, वित्तीय प्रणालियां थरथराती हैं और डिजिटल नेटवर्क एवं समुद्री मार्ग रुकते हैं. प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हमारे अस्तित्व के हर पहलू तक फैल चुका है, लेकिन शासकीय सिद्धांत अभी भी 17वीं सदी के 'वेस्टफेलियन संप्रभुता' के तर्क में अटके हैं. हम बाड़ लगाने के औज़ारों से बाढ़ नियंत्रण में लगे हैं.

मूल अंतर्दृष्टि : निरंतरता के रूप में स्थिरता- इतिहास एक शांत सत्य उजागर करता है : स्थिरता निरंतर आदान-प्रदान होते रहने से बनती है, न कि प्रतिद्वंद्विता के अभाव से. मार्ग मुक्त रहें और आवाजाही सुरक्षित रहे, तो दुनिया समृद्ध होती है. जब ये प्रवाह थम जाए, तो पतन होता है. स्थिरता प्रवाह संग चलती है. यह हमारा गंतव्य न होकर वह गति है जिसे बनाए रखना होता है- जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शिनाख्त की थी, न कि आविष्कार. हमारे समय के व्यवधान एक अंतर्निहित नियम उजागर करते हैं : स्थिरता प्रवाह की निरंतरता के पीछे-पीछे आती है. यह तर्क कोई नया नहीं. भौतिकी इसे काफी पहले कायम कर चुकी है. प्रवाह को प्रतिरोध द्वारा संरक्षित किया व बनाया जाता है,और अंतर से प्रवाह काम करता है. एकदम बांध दें, तो दबाव कहीं और बन जाएगा. तोड़ दें, तो तबाही मच जाएगी. ग्लोबल सिस्टम का व्यवहार भी इससे अलग नहीं.

इस्लामाबाद वार्ता : मिसाल कायम करने का मौका गंवाया: इस्लामाबाद में बहुत बड़े दांवों वाली वार्ता में, मिसाल कायम करने का अवसर गंवा डाला. सप्ताहों तक बढ़ती गई तनातनी के बाद दोनों पक्ष मिले. अपनी-अपनी स्थिति का बचाव करते रहे, इतिहास का हवाला दिया, और रेड लाइंस खिंची. लेकिन वे खाली हाथ लौटे. जो कुछ हुआ, वह कोई वार्ता नहीं रही; यहां एक मिसाल कायम करने का मौका गंवा दिया. दोनों पक्षों को आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ की सर्वाधिक ज़रूरत थी, उनमें से कुछ भी सामने नहीं रखा. वार्ताकार आगे की राह टटोलने की बजाय अपनी-अपनी स्थितियां न्यायोचित ठहराने तक सीमित रहे. वे विरोधी के रूप में मिले. चाहते तो 'प्रवाह के संरक्षक' के रूप में लौट सकते थे. लेकिन ऐसा नहीं किया. जब गौरव या ज़मीन के मुद्दे पर बातचीत हो, तो हम वहीं अटक जाते हैं. जब अस्तित्व की साझा जीवन-रेखाओं पर बात करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे.

क्षैतिज गुरुत्वाकर्षण : नया स्थिरांक- अब हम किसी के सिंहासन के आकार या सीमा बहुत दूर होने से अधिक प्रभावित नहीं. नया स्थिरांक है आपसी निर्भरता; अदृश्य खिंचाव, जो ऊर्जा मार्ग, डेटा नेटवर्क और वित्तीय प्रणालियों को एकीकृत कार्यशील हकीकत में बांधता है. लंबवत ऊंचाई के लिए जैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है, वही काम क्षैतिज दिशा में प्रवाह का है. यह आम सहमति का इंतज़ार नहीं करता, न ही किसी आचार-संहिता से चालित है;यह तो बाध्यकारी है. पारस्परिक निर्भरता को हम नहीं चुनते; बल्कि इसी संग जन्म लेते हैं. आधुनिक राष्ट्र के लिए प्रवाह को नकारना ऑक्सीजन को नकारने जैसा है.

प्रवाह का सिद्धांत : प्रकृति का प्रथम नियम- प्रवाह प्रकृति का प्रथम नियम है: निरंतरता से ही स्थिरता बनी रहती है; इसमें आया व्यवधान प्रणालियों को पुनः अराजकता की ओर धकेल देता है. अगले दशकों में जीवित रहने के दायित्व का तालमेल निर्भरता से बैठाना होगा. जरूरी प्रवाह रुके नहीं.

खुले मार्गों से साझा नियमों तक : समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि गहरे समुद्र जैसे कुछ क्षेत्र खुले रहने चाहिए. इस प्रावधान ने पहुंच संरक्षित रखी; लेकिन निरंतरता सुनिश्चित नहीं की. प्रवाह का नियम इसमें अनिवार्य सुधार होना चाहिए. तब यह पहुंच को दायित्व में बदल देगा: परस्पर जुड़ी दुनिया में, मार्ग न केवल खुले, बल्कि कार्यात्मक भी रहें. अहम मार्गों का प्रवाह रोकने से फायदा नहीं होता; यह तो प्रणालीगत जोखिम है. यदि यह सिद्धांत इस्लामाबाद में हुई चर्चा में रखा होता, तो वार्ता अपनी-अपनी स्थिति का बचाव करने से हटकर मार्गों पर स्थिति की ओर मुड़ जाती व मिसाल कायम होती- समझौते के लिए नहीं, निरंतरता के लिए.

साझापन में विस्तार : साझापन की जरूरतें बदल चुकी हैं. वे अब केवल महासागर व वायुमंडल तक सीमित नहीं ; उनमें अब ऊर्जा गलियारा, व्यापारिक जलमार्ग और इंटरनेट की फाइबर-ऑप्टिक शामिल हैं. ये संपत्तियां न होकर जीवित रखने योग्य जीवन-रेखाएं हैं. इन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो; इनकी देखभाल हो. इनमें पड़े व्यवधान का असर वैश्विक स्तर पर होता है क्योंकि परस्पर निर्भरता एक योजना है, विकल्प नहीं. आवश्यकता संप्रभुता के समर्पण की नहीं बल्कि निरंतरता की रक्षा करने वाले मानदंडों का विस्तार करने की है. किसी संकरे अहम मार्ग का संरक्षक मात्र एक द्वारपाल न होकर वैश्विक नब्ज की धड़कन का संरक्षक बने.

जिम्मेदारी और परिणाम : परिणामहीन कानून मात्र एक सुझाव है. निवेश : चाहे मलक्का स्ट्रेट हो या वैश्विक डेटा नेटवर्क, इनका प्रवाह सुनिश्चित करने वालों को ठोस प्रतिफल मिले. स्थिरता बनाए रखना एक सेवा है; इसका महत्व समझा जाए. सुधार : सामरिक लाभ के लिए ये प्रवाह रोकने वालों के लिए स्वतः स्फूर्त सामूहिक परिणाम भुगतने का प्रावधान बनाया जाए. ये उपाय दंडात्मक न होकर, सुधारात्मक होंगे. उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि प्रवाह बहाल रखना है.

संघर्ष से निरंतरता की ओर : यह आदर्शवाद नहीं, अपने सबसे अनुशासित रूप में यथार्थवाद है. प्रवाह का नियम टकराव खत्म नहीं करता; उसका दायरा सीमित करता है. यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंद्विता मानव अस्तित्व की प्रणालियों को बंधक न बना पाए. स्थिरता निरंतरता की उपस्थिति है, न कि संघर्ष का अभाव. विश्व के संकरे मार्गों में, होर्मुज़ हो ,स्वेज हो या क्लाउड डाटा, वहां बनी निरंतरता जो स्थिरता दे सकती है, वह सियासी रूप से संभव नहीं. साझा निर्भरता से बंधे राज्य मानदंड तय कर सकते हैं और बोझ बांट सकते हैं, उपयोगिता के जरिये व्यवस्था बने, एक केंद्रीय प्रबंधन बनने की प्रतीक्षा न करें.

लापता कड़ी : प्रवाह के संरक्षक : संरक्षकों के बिना कोई सिद्धांत टिक नहीं सकता. मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर होर्मुज़ और स्वेज तक, और आगे डिजिटल युग के अदृश्य द्वारों तक, निरंतरता के मार्ग अपने स्वाभाविक संरक्षकों को प्रकट कर चुके हैं. अस्पष्ट संघर्ष के इस युग में, व्यवधान शायद ही कभी स्वयं को घोषित करे. जलडमरूमध्य से आवाजाही पूरी थमने की बजाय धीमी हो जाती है. नेटवर्क रुकता नहीं, क्षीण होता है. दोषारोपण में देरी होती है और जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. फिर भी प्रभाव वही होता है: लड़खड़ाया प्रवाह, और साथ ही स्थिरता भी.

इसलिए, प्रवाह के नियम को इसे लागू करवाने वालों की एक नई श्रेणी हो : निरंतरता के संरक्षक. ये पारंपरिक अर्थों में गठबंधन नहीं , न ही दबाव बनाने के औजार. ये तो पूर्व-निर्धारित जिम्मेवार राष्ट्र अथवा उनका गठबंधन है, जिन्हें समुद्री अवरोध बिंदुओं, ऊर्जा गलियारों या डिजिटल नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रवाहों की तत्काल बहाली का कार्य सौंपा गया हो. उनका जनादेश सीमित है; उनकी वैधता शक्ति से चालित न होकर कार्य से प्राप्त होती है. इसे संभव बनाने के लिए, प्रवाह को वैश्विक सेवा के रूप में मान्यता मिले. इसे सुरक्षित रखने वालों को मुआवजा दिया जाए. बाधित करने वालों के लिए स्वचालित, सामूहिक प्रतिक्रिया तंत्र स्वतः सक्रिय हो जाए, जो त्वरित हो, नियमाधारित एवं सियासी विलंबों से मुक्त हो. इस ढांचे से संप्रभुता कम नहीं होगी. यह परस्पर निर्भरता से अनुशासित होगी. प्रवाह टूट जाने पर, आम सहमति की प्रतीक्षा न की जाए. इसे योजनाबद्ध ढंग से बहाल किया जाए

निष्कर्ष : गतिरोध का खतरा - इतिहास ने मार्ग खोले हैं. कानून ने उन्हें संरचना दी. वर्तमान समय की मांग है उनकी निरंतरता बनाए रखना. प्रवाह का सिद्धांत सियासी गतिरोध से परे है. यह भौतिकी जैसी सटीकता से कार्य करता है. हम संप्रभुता को अलगाव समझने की गलती करते हैं. यदि उत्तरदायित्व की अनुरूपता निर्भरता के अनुसार नहीं तो व्यवस्था भंग हो जाएगी. इस सदी में, शक्ति का मापन इससे नहीं होगा कि राष्ट्र क्या नियंत्रित करने की ताकत रखते हैं, बल्कि इससे होगा कि किसका प्रवाह सुचारु है. जो प्रवाह बना रहना अनिवार्य है, थमने न पाए. ***(लेखक सेना की पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर एवं पुणे इंटरनेशनल सेंटर के संस्थापक ट्रस्टी हैं)***

आपका जन्मदिन मंगलमय हो

17 अप्रैल

आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. आपका जन्मतिथि 17 अप्रैल है. अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्मतिथि का स्वामी ग्रह शनि है. इस माह का अधिपति ग्रह मंगल है. आपके ऊपर मंगल एवं शनि ग्रह का प्रभाव आजीवन रहेगा. आपकी महत्वकांक्षाएँ बहुत ऊँची होगी. आप सहज ही कुछ भी प्राप्त नहीं कर पायेंगे, जीवन में कई बार उतार-चढ़ाव के क्षण आयेंगे. लेकिन आप सामान्य रूप से ही कार्य करना पसन्द करेंगे. आप भौतिकवादी दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व देंगे. आप ऊपर से कठोर होते हुए भी अन्दर से अत्यन्त कोमल व दयालु प्रवृत्ति के होंगे. मित्रों के लिए आप अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन शत्रुओं के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं रहेगी. सूक्ष्मदर्शिता आपका विशेष गुण होगा. आप अनुशासन के प्रति कठोर रूख अपनायेंगे. आपके जीवन में आकस्मिक लाभ के क्षण भी आयेंगे. आपको क्षण में ही सफलता क्षण में ही असफलता का सामना करना पड़ेगा. सुख-समृद्धि हेतु नियमित रूप से देव अर्चना करें. काले रंग की वस्तुओं का दान करें. गाय को नियमित रूप से घी लगा हुआ रोटी खिलावें. हिंसा जनित कार्य न करें. आरोग्य व सौभाग्य के लिए रत्न या उपरत्न तथा यन्त्र विधि-विधानपूर्वक धारण करें.

आपके लिए अनुकूल :-

मन्त्र	:	ॐ शं शनैश्चराय नम:	मास	:	जनवरी, अप्रैल एवं दिसम्बर
व्रत	:	शनिवार	वर्ष	:	8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71
दिन	:	सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार	रंग	:	हरा, नीला, काला एवं भूरा
दिनांक	:	8, 17, 26	जन्मरत्न	:	नीलम
अंक	:	2, 4, 6, 7	उपरत्न	:	नीली

यंत्र

12	7	14
13	11	9
8	15	10

वर्ष का महत्वपूर्ण समय – 20 जन. से 20 फर., 20 सित. से 20 अक्टू.

हस्तरेखा विशेषज्ञ, रत्न-परामर्शदाता, फलित व अंक ज्योतिषी एवं वास्तुविद

विमल जैन एस. 2/1-76 ए, द्वितीय तल, वरदान भवन, पंचक्रोशी मार्ग, भोजूबीर, वाराणसी-221002 मो0 : 09335414722

आपका आज का दिन 2026

मेष : आज दिन 12/03 बजे तक विपरीत, राजकीय पक्ष से उलझनें, मित्रों से अनबन, विचारों में उग्रता, शेष समय में व्यावसायिक उन्नति, समस्या का समाधान पक्ष में.

वृषभ : आज दिन 12/03 बजे तक सफलताजनक व सम्पर्क उपयोगी, आरोग्य सुख, यात्रा सुखद, शेष समय में लाभार्जन में व्यवधान, कार्यों में निराशा, आत्मबल में कमी.

मिथुन : वाक्पटुता से संकल्प सिद्धि, जिम्मेदारियों को निभाने हेतु व्यय, सामयिक कृत्यों से यश की प्राप्ति, जनकल्याण की भावना जागृत, दर्शनीय स्थलों की यात्रा.

कर्क : कार्य-व्यवसाय में परिश्रम के अनुरूप सफलता, पराक्रम में वृद्धि, आपसी सलाह से कामयाबी, पारिवारिक वातावरण में हर्षोल्लास, चित्त प्रफुल्लित.

सिंह : आज दिन 12/03 बजे तक भाग्य में न्यूनता, समस्याओं से चिन्तित, उन्नति में बाधा, प्रेम सम्बन्धों में कटुता, शेष समय में नवयोजना फलीभूत,पारिवारिक सुख.

कन्या : आज दिन 12/03 बजे तक समय प्रगतिकारक, व्यक्तिगत परेशानी कम, इच्छा शक्ति जागृत, यात्रा सुखद, शेष समय आरोग्य सुख में कमी, कार्यों में अड़चनें.

तुला : बहुप्रतीक्षित कार्यों के बनने से प्रसन्नता, आर्थिक समस्या का निवारण, आपसी सौहार्द, दूसरों के आश्वासनों से मानसिक राहत, शुभ भावनाओं का उदय.

वृश्चिक : व्यापार में धन निवेश, शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता, मित्रों में उपस्थित गलतफहमियां दूर, धन सम्पत्ति विषयक मसला पक्ष में सुलझने को.

धनु : आज दिन 12/03 बजे तक समय अशुभ, निर्णय लेने में परेशानी, स्पष्टवादिता घातक, तनाव भी, शेष समय अनुकूल, मनोरथ की सिद्धि, भौतिक सुख प्राप्त.

मकर : आज दिन 12/03 बजे तक दिनमान पक्ष में, पराक्रम से कुछ कार्य बनने को, सुयश की प्राप्ति, शेष समय विपरीत, समस्याएँ प्रभावी, जिम्मेदारियों को निभाने में मुश्किलें.

कुम्भ: परिस्थितियों में क्रमिक सुधार, नवयोजना का शुभारम्भ, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, राजनैतिक गतिविधियों में अभिरुचि, आमोद-प्रमोद के साधन सुलभ.

मीन: शारीरिक सुख, स्वविवेक से लिया गया निर्णय हितकर, विवादास्पद मसला सुलझने की ओर, मान-सम्मानपरक कृत्य सम्पन्न, प्रेम सम्बन्धों में प्रगाढ़ता.

- ज्योतिषाचार्य विमल जैन, वाराणसी, मो. नं. 09335414722

मानव धर्म-शास्त्र

लेखक : लक्ष्मी नारायण मीणा

मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता
अवधूत देवी दास जी महाराज

अष्टम स्कन्ध

जन्मत सुत रां उच्चारी । पीड़ा प्रसव विगत महतारी ।।
चहुँदिसि भयउ प्रकृति उछाहु । मंगल सुगन अनुकूल सबाहु ।।

व्याख्या - जन्म लेते ही पुत्र ने रां नाम का उच्चारण किया, जिससे माता की प्रसव पीड़ा तुरन्त दूर हो गई । चारों तरफ प्रकृति में उत्साह छा गया तथा समस्त मंगलकारी सगुन होने लग गए ।

समाचार सुनि ऋषि सब आए । देखि मुख छवि आशीष बरसाए ।।
बालक इहँ होइब ब्रम्ह ग्यानी । सकल ऋषि मुनि कहा बखानी ।।

व्याख्या - समाचार सुनकर सब ऋषि आए और बालक की छवि देखकर आर्शीवाद देने लगे । सब ऋषि - मुनियों ने कहा कि यह बालक ब्रम्हज्ञानी होगा ।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार की अनिवार्यता का विमर्श

–डॉ. मयंक चतुर्वेदी

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से एक व्यापक सामाजिक, वैचारिक और लोकतांत्रिक संघर्ष का मंच रही है. इस बार भी 2026 के विधानसभा चुनाव इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक निर्णायक मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. अब यह चुनाव ही तय करेगा कि राज्य में लोकतंत्र की गुणवत्ता, जवाबदेही और संस्थागत मजबूती किस दिशा में आगे बढ़ेगी. ऐसे परिदृश्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है. दरअसल, पिछले एक दशक में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण देखने को मिला है. 2011 में परिवर्तन की उम्मीदों के साथ सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत में जनसमर्थन अर्जित किया, लेकिन समय के साथ यह शासन शैली एक व्यक्ति-केन्द्रित प्रशासन में बदलती चली गई. प्रशासनिक निर्णयों में संस्थाओं की भूमिका सीमित होती गई और राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र के बीच की दूरी कम होकर पक्षपातपूर्ण होते हुए दिखी. हालांकि ममता का राज इसी विश्वास पर बहाल हुआ था कि पश्चिम बंगाल से अराजकता की समाप्ति होगी, बांग्लादेश से होनेवाली घुसपैठ रुकेगी और हिंसा बंद होकर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. पर हकीकत में क्या हुआ ? यही कि वादों के अनुरूप ममता सरकार कुछ नहीं कर पाई, उल्टा यह सामने आया कि संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही समाप्त हो गई. ममता सरकार अपनी हर आलोचना को दबाने लगी. विपक्ष को हाशिए पर धकेल दिया गया और प्रशासनिक मशीनरी को राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. स्वभाविक है कि सभी संकेत लोकतंत्र के लिए खतरे के हैं. राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार सवालों के घेरे में है. आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ जघन्य अपराध हम सभी ने देखा, कैसे एक प्रशासनिक संवेदनहीनता और जवाबदेही के अभाव का प्रतीक बन कर सामने आया है. ऐसे मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया ने यह संदेश दिया कि ममता सरकार जनता की सुरक्षा से अधिक अपनी छवि बचाने में रुचि रखती है. इसके अतिरिक्त, राजनीतिक हिंसा की घटनाएं, जोकि बंगाल की राजनीति का एक पुराना दाग रही हैं, अब भी समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि कहना चाहिए ममता राज आने के बाद इसमें बढ़ोत्तरी ही हुई है. चुनावी प्रक्रिया में हिंसा, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले और मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोप लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं.किंतु इस बात की फिकर किसे है! ममता का अपना अब तक फिक्स हो चुका वोट का चुनावी गणित है. इसलिए ही ममता सरकार की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक उसकी वोट बैंक आधारित राजनीति रही है. यहां उल्लेखित है कि राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 28-29 फीसद है और लंबे समय तक एकमुश्त वोटिंग के कारण यह एक निर्णायक राजनीतिक कारक बनी रही है. कहना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस ने इस समीकरण को कुशलता से साध रखा है, किंतु इसके परिणामस्वरूप नीति-निर्माण में संतुलन की कमी दिखाई देती है, राज्य का जो समग्रता के साथ विकास होना चाहिए, वह जैसे अब भी इस राज्य के लिए एक स्वप्न जैसा है. पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुस्लिम विशेषकर बहुसंख्यक हिन्दुओं पर हावी दिखता है. इस प्रकार की राजनीति ने समाज में विभाजन की भावना को जन्म दिया है, जिसमें कि एक ओर जहां लगातार ममता सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय में असंतोष बढ़ा है. इसलिए यहां का अधिकांश बहुसंख्यक समाज सत्ता का बदलाव चाहता है. इसका एक आधार फिर चुनावी आंकड़े भी हैं, जोकि इस बदलाव की पुष्टि करते हैं. 2011 में 38.93 फीसद वोट से 184 सीटें, 2016 में 45 फीसद वोट से 211 सीटें और 2021 में 48 फीसद वोट से 213 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस अब नए राजनीतिक समीकरणों से जूझती दिख रही है. वस्तुत: 2023 के सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत और 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी का पारंपरिक वोट बैंक अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा. इससे यह स्पष्ट होता है कि एकमुश्त वोट का पुराना गणित टूट रहा है. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़त बनाना भी ममता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. 2014 में मात्र 17 फीसद वोट पाने वाली भाजपा ने 2019 में 41 प्रतिशत वोट और 18 सीटें हासिल की थीं. 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटों के साथ वह मुख्य विपक्ष बनकर उभरी. इसके अलावा, कांग्रेस-वाम गठबंधन भी अपनी खोई जमीन वापस पाने का प्रयास कर रहा है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकला चलो रणनीति और वाम दलों का पुनर्गठन यह संकेत देता है कि बंगाल की राजनीति अब बहुकोणीय संघर्ष में बदल चुकी है. एक तरह से देखें तो यह प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह सत्ता के एकाधिकार को चुनौती देती है. इसके साथ ही जिस तरह से इस बार मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का कार्य हुआ है और लगभग 58 लाख नामों का प्रारंभिक सूची से बाहर होना, यह बताता है कि अब तक जिस अवैध वोट बैंक के सहारे ममता की पार्टी राज्य की कई सीटों पर जीत दर्ज करती रही, इस बार वह चमत्कार करना आसान नहीं होगा. घुसपैठ और नागरिकता के प्रश्न पर सरकार का अस्पष्ट रुख भी यहां आम जन में आलोचना का विषय है. यह मुद्दा कहना होगा कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण से जुड़ा है. ममता सरकार पर प्रतीकात्मक हिंदुत्व अपनाने के आरोप भी लगते हैं, जैसे कि मंदिर उद्घाटन, दुर्गा पूजा को प्रोत्साहन आदि लेकिन आलोचकों का इस बारे में स्पष्ट मानना है कि ममता के द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के कार्य बांग्ला संस्कृति के लिए वास्तविक सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं हैं, यह उनकी चुनावी रणनीति है. बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का वर्तमान राजनीतिक माहौल में लगातार क्षरण हो रहा है. ऐसे में कहना यही होगा कि ममता बनर्जी का शासन, जोकि कभी परिवर्तन का प्रतीक था, अब कई मायनों में ठहराव, केंद्रीकरण और विवादों का पर्याय बन चुका है. हिंसा उसके केंद्र में है. अनेक बड़ी हिंसात्मक घटनाएं जैसे आज पश्चिम बंगाल की नीयति बन गई लगती हैं. स्वभाविक है इस संदर्भ में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की आवश्यकता बन गया है. यदि जनता को लगता है कि शासन उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा, तो परिवर्तन ही लोकतंत्र का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम होता है. 2026 का चुनाव इसी परिवर्तन की संभावना का प्रतीक बनकर सामने दिखाई दे रहा है. यह चुनाव तय करेगा कि क्या बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के अनुरूप एक अधिक जवाबदेह, समावेशी और संतुलित राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा या फिर वर्तमान व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगा. आखिर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता है और उसे ही यहां तय करना है कि बंगाल का भविष्य किस दिशा में जाए!

न्यूज कॉर्नर

नगर परिषद अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष का उद्घाटन हुआ

साहिबगंज : नगर परिषद कार्यालय स्थित नगर परिषद अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष का सोमवार को मुख्य अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने नारियल फोड़ व फीता काट कर किया उद्घाटन। इसके पूर्व मुख्य अतिथि सहित नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान, नगर प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह व सभी वार्ड पार्षदों व कर्मियों ने नगर परिषद परिसर में मौजूद बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। उद्घाटन के उपरांत कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जहां नगर अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया। वहीं नगर प्रशासक ने मुख्य अतिथि व नगर परिषद अध्यक्ष का बुके देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष ने कार्यालय कक्ष के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि इससे अध्यक्ष, सभी वार्ड पार्षदों, कर्मियों व जनता को सुविधा होगी। नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान ने कहा कि उनका कार्यालय जनता का कार्यालय है। उन्होंने जनता की सेवा की ठानी है।लोग बेझिझक उनके कार्यालय कक्ष में अपनी समस्या लेकर आएं। सभी समस्याओं के समाधान का यथासंभव समाधान किया जाएगा। मौके पर सिटी मैनेजर रवि कुमार, सभी वार्ड पार्षद,सिटी, लेखा पदाधिकारी कुमारी पूर्णिमा, सोनू हरि, शिव हरि, राकेश, सहित अन्य थे।

समीप वाहन जांच अभियान चलाया

तालझारी : जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी के नेतृत्व में तालझारी थाना क्षेत्र के शहीद चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस अभियान में बिना हेलमेट मोटरसाईकिल चला रहे लोगों व चारपहिया वाहनों का चालान काटा गया.जिसमें दर्जनों वाहन से कुल 55 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया. समाचार लिखे जाने तक वाहन जांच अभियान जारी रहा. जांच करने आये पदाधिकारी ने वाहन जांच के द्वौरान वाहन चालकों को अपने वाहन का पूरा कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस साथ ले कर चलने की अपील की बीना कागजात के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जायेगा. इसके अलावा उन्होने यातायात नियमों का भी पालन करने की अपील की. कहा कि ओवर स्पीड बाइक चलाना या सड़क पर किसी प्रकार का स्टंट करने वालों को पकड़ कर कार्रवाई की जायेगी वहीं नाबालिक को वाहन चालते पकड़े जाने पर उनके परिजनों पर कार्रवाई की जायेगी.मौके पर जिला सडक सुरक्षा प्रबंधक निरंज कुमार साह, रोड इंजिनियर एनालिशट अनुज प्रसार, आदि सहित अन्य पुलिस अधिकारी जवान मौजूद थे।

कैरासोल-बांझी सड़क पर बालू लदा 16 चक्का हाइवा पलटा, चालक फरार

तालझारी : थाना क्षेत्र के कैरासोल-बांझी मुख्य सड़क पर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। कैरासोल गांव के समीप एक तीव्र घुमाव (मोड़) पर बालू से लदा एक 16 चक्का हाइवा रजिस्ट्रेशन नंबर: गक16 ऋ 2937 अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार की देर रात की बताई जा रही है। हाइवा बांझी की ओर से बालू लादकर कैरासोल की तरफ आ रहा था। इसी दौरान कैरासोल गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित घुमावदार मोड़ के पास चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित हाइवा सड़क किनारे लगी सुरक्षा लेरिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा और पूरी तरह पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया।गुरुवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही तालझारी थाना प्रभारी नितेश कुमार पांडेय दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और मामले की छानबीन शुरू की।इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भारी मात्रा में यह बालू कहाँ ले जाया जा रहा था। अभी तक बालू के स्वामित्व और उसके गंतव्य स्थान के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच में जुट गई है।

बाइक दुर्घटना में एक युवक घायल

मण्डरो : प्रखंड अंतर्गत मिर्ज़ाचौकी-भगैया मुख्य पथ पर गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार गोखला मिशन के समीप मुख्य सड़क पर दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई।दुर्घटना में मोटरसाइकिल संख्या जेएच 17 एल 4440 पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार वाहन सहित मौके से फरार हो गया।घायल की पहचान अजय लोहरा,निवासी मोहबी, थाना पिरपैती के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया।

देसी फ्रिज की बड़ी बिक्री बाजारों में मिट्टी के घड़ों की जबरदस्त मांग

पाकुड़:गर्मी का पारा चढ़ते ही बाजारों और साप्ताहिक हाटों में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़ों की मांग तेजी से बढ़ गई है। हाटों में इन दिनों मिट्टी के बर्तनों की बिक्री में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में मिट्टी के घड़े और अन्य बर्तन खरीद रहे हैं। मटके का पानी न सिर्फ ठंडा रहता है, बल्कि उसका स्वाद भी सामान्य पानी की तुलना में अधिक बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि हर वर्ग के लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए कुम्हार भी अलग-अलग डिजाइन और आकार के घड़े तैयार कर रहे हैं। हालांकि, कच्चे माल और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के कारण घड़ों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वर्तमान में एक घड़े की कीमत 100 से 400 रुपए तक है।

जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल को जिले के 15 केंद्रों पर, 5700 परीक्षार्थी होंगे शामिल

सफल संचालन को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने की संयुक्त समीक्षा बैठक

पाकुड़:आगामी 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (जेपीएससी) 2025 के सफल एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 15 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें लगभग 5700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा- प्रथम पाली: पूर्वाह्न 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक द्वितीय पाली: दोपहर 3:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक। उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा को पूर्णतः कदाचार मुक्त एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए-सभी केंद्रों पर पर्याप्त बेंच, डेस्क, पेयजल, शौचालय एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रवेश द्वार पर सिटिंग अरेंजमेंट चार्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया। सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उड़नदस्ता टीम द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा।

कालियागंज में कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा झंडे को लेकर भारी तनाव

उत्तर दिनाजपुर : कांग्रेस कार्यालय में भाजपा का झंडा लगाए जाने को लेकर गुरुवार सुबह उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में तनाव फैल गया। आरोप है कि रात के अंधेरे में कालियागंज शहर के तालतला स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा का झंडा लगा दिया गया। गुरुवार सुबह कार्यालय के सामने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। भाजपा का झंडा हटाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हो गई।घटनास्थल पर केंद्रीय बल और पुलिस पहुंची। घटना के विरोध में कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पुराने मोबाइल का दुरुपयोग बन सकता है साइबर खतरा सतर्क रहने की सलाह

पाकुड़ आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन जहां दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, वहीं इसके दुरुपयोग के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र में हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पुराने या खोए हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल साइबर अपराध में किए जाने की आशंका जताई गई है। इसको लेकर पाकुड़िया थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अपने पुराने मोबाइल फोन किसी कबाड़ी या फेरीवाले को बिना सोच-विचार के न दें और यदि फोन खो जाए तो तुरंत थाना में सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई करें। **पुराने मोबाइल से साइबर अपराध का खतरा:** सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में कुछ कबाड़ी या फेरीवाले लाउडस्पीकर के माध्यम से पुराने मोबाइल के बदले बर्तन जैसी पेशकश कर लोगों से मोबाइल एकत्र कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे मोबाइल आगे साइबर अपराधियों के हाथों में पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इन पुराने मोबाइलों को ठीक कर फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मोबाइल अभी भी किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो जांच के दौरान उसे कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।**निजी डेटा की सुरक्षा पर भी खतरा:** पुराने मोबाइल में मौजूद व्यक्तिगत डेटा भी बड़ा जोखिम बन सकता है। कई लोग बिना डेटा डिलीट किए ही फोन कबाड़ी को दे देते हैं, जिससे कॉन्टैक्ट, मैसेज, फोटो, बैंकिंग ऐप्स और अन्य निजी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में साइबर ठगी और पहचान के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि पुराने मोबाइल को देने से पहले उसका पूरा डेटा मिटाकर फैक्ट्री रीसेट किया जाए। संभव हो तो फोन को अधिकृत रीसाइक्लिंग सेंटर या भरोसेमंद माध्यम से ही नष्ट किया जाए।

दसवीं बोर्ड में 11 छात्र-छात्राओं के अंक 92 % से अधिक

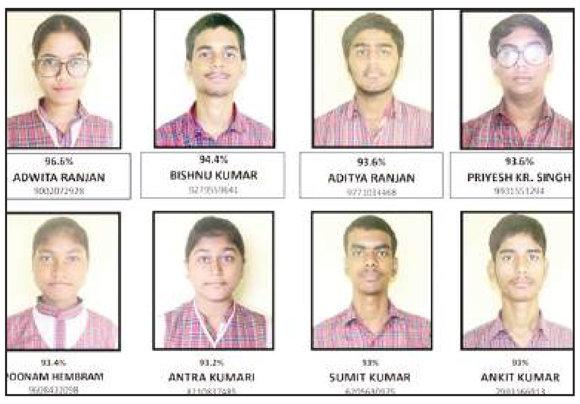

पाकुड़: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। डीएवी पब्लिक स्कूल गोकुलपुर पाकुड़ 11 छात्र छात्राओं ने 92 प्रतिशत से अधिक अंक लाकर अपने माता-पिता व गुरुजनों एवं विद्यालय का नाम रोशन किया है। इनमें अद्विन्ता रंजन 96.6%,बिष्णु कुमार94.4%, आदित्य रंजन 93.6%, प्रियेश कुमार सिंह 93.6%, पूनम हेंब्रम93.4%, अंतरा कुमारी 93.2%, सुमित कुमार93%,अंकित कुमार 93% सीरिया विद्यार्थी90.4% , अस्ता सिंह91.4%मोनिक अग्रवाल92% अग्रणीय श्रेणी में है। इन सभी छात्र-छात्राओं आपस में खुशी जाहिर करते हुए अपने माता-पिता एवं गुरुजनों को नमन किया है। छात्रों के माता-पिता ने बताया है की छात्रों की लगन और गुरुजनों का आशीर्वाद का यह फल है। छात्र-छात्राओं ने आगे की पढ़ाई और अच्छी तरह से करने का संकल्प लिया है।

तृणमूल प्रत्याशी के पोस्टर फाड़ने का आरोप, इलाके में सनसनी

जलपाईगुड़ी : तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी स्वप्ना बर्मन के समर्थन में लगाए गए पोस्टर फाड़ने की घटना को लेकर गुरुवार को इलाके में सनसनी मच गया। घटना राजगंज ब्लॉक के पानीकौड़ी ग्राम पंचायत के बांशबाड़ी इलाके की है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से स्वप्ना बर्मन के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। साथ ही पार्टी के झंडों को भी जलाने का दावा किया गया है।राजगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अरिंदम बनर्जी ने इस मामले में सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया है।उनका कहना है कि भाजपा से जुड़े लोग योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न इलाकों में तृणमूल के पोस्टर फाड़ रहे है और बांशबाड़ी में भी ऐसी ही घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी।

संत पॉल पब्लिक स्कूल के छात्र सीबीएसई 10 वीं में जिले में हुये अव्वल

तेघड़ा/बेगूसराय (युवा शक्ति ब्यूरो) : सीबीएसई 10 वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में संत पॉल पब्लिक स्कूल, तेघड़ा के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये एक बार फिर पूरे जिले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। विद्यालय के कुल-215 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुये, जिनमें से 21 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस वर्ष उत्कर्षा रंजन ने 96.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अर्नव झा (95%), आयुष कुमार पंडित (94%), साक्षी कुमारी (93.5%), स्वेत (93%), सौम्य साहू (93%), स्तुति आनंद (93%), सत्यजीत (92%), निखिल (92%), आयुषी (91.5%), अनिकेत राज (91%) एवं श्रेया भरद्वाज (90%) सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के 43 विद्यार्थियों ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये, जबकि शेष सभी छात्र-छात्राएं अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुये।विद्यालय के

निदेशक सुनील कुमार सिंह ने इस सफलता का श्रेय प्राचार्य के कुशल नेतृत्व, शिक्षकों की मेहनत एवं विद्यार्थियों की लगन को दिया। संत पॉल एजुकेशनल सोसायटी के सचिव रामबली सिंह ने सफल विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुये कहा कि ये बच्चे भविष्य में देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।विद्यालय की प्रेसिडेंट लक्ष्मी कुमारी ने सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्राचार्या तनु सौरव ने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों की प्रतिभा को दिया। विद्यालय के इस उत्कृष्ट परिणाम से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। स्थानीय बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों ने इसे क्षेत्र के लिये गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक राम कुमार मिश्रा, रंजीत कुमार, संजीव कुमार सिंह, त्रिपुरारी कुमार सिंह, रंजन कुमार, राज किशोर, एस. रामचंद्रन, राम पुनीत राय, कंचन कुमारी, प्रेम माधुरी, राकेश कुमार, संजीत कुमार, भारती कुमारी सहित अन्य शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी एवं अभिभावक उपस्थित थे।

चाय बागान क्षेत्रों में बढ़त के लक्ष्य के साथ उतरे तृणमूल प्रत्याशी निर्मल चंद्र राय

जलपाईगुड़ी : आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है। इसे देखते हुए धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर निर्मल चंद्र राय ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है।मतदान में अब कुछ ही दिन शेष रहने के कारण वह अंतिम चरण में प्रचार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। गुरुवार सुबह से ही उन्होंने चाय बागान क्षेत्र बनारहाट में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन चाय बागान क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को अपेक्षित बढ़त नहीं मिल सकी थी।प्रचार के दौरान निर्मल चंद्र राय ने विभिन्न चाय बागानों में जाकर श्रमिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं व शिकायतें सुनीं।

गंगा नारायण सिंह जयंती समारोह के लिए मुख्यमंत्री को भूमिज समाज ने दिया आमंत्रण

जमशेदपुर : आगामी 25 अप्रैल को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की 236वीं जयंती समारोह को लेकर भूमिज समाज के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड मंत्रालय, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। इस दौरान पोटका विधायक संजीव सरदार भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल में संजय सरदार, हिमांशु सिंह, राधेश्याम भूमिज, ईश्वर लाल सरदार, अमर सिंह भूमिज अमल सरदार, सागर सरदार, प्रोरंजन सरदार, तथा भुगुराय सरदार शामिल थे। इस दौरान कार्यक्रम के महत्व और इसकी व्यापक तैयारियों की भी जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से भी मुलाकात कर उन्हें जयंती समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने सभी अतिथियों से कार्यक्रम में भाग लेकर समाज का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। आयोजन समिति के अनुसार 25 अप्रैल को होने वाला यह समारोह ऐतिहासिक और भव्य होगा, जिसमें सिंहभूम के तीनों जिलों सहित अन्य राज्यों से भी 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में सुबह पूजा-अर्चना एवं विचार गोष्ठी, दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा शाम को विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समाज की परंपराओं को प्रदर्शित करने हेतु स्टॉल भी लगाए जाएंगे

सीपी, डीएम और सीएपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से इलाके का दौरा किया

आसनसोल: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को जिला दंडाधिकारी (डीएम), पुलिस आयुक्त (सीपी) तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अपर चेलीडंगाल इलाके का दौरा किया. इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आम मतदाताओं से सीधे बातचीत किया.निरीक्षण के दौरान डीएम और सीपी ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया. अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं को सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने का पूरा अधिकार है और प्रशासन इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार के दबाव, डर या प्रलोभन से दूर रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें.संयुक्त टीम ने इसके बाद उत्तर थाना क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि अगर मतदान के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या कोई असामाजिक तत्व बाधा डालने की कोशिश करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. इसके लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिस पर संपर्क कर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है.प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सीएपीएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. इस संयुक्त दौरे का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के बीच विश्वास कायम करनो हैं,

विधायक सरयू राय ने कहा- पुलिस गिरोह का पर्दाफाश करे, सरगना

जमशेदपुर/रांची : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय का कहना हैं कि रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया है कि जन्मदिन मनाने के बहाना से डेंटल छात्रा के साथ व्यभिचार करने वालों और इसकी साज़िश रचने वालों को कड़ी सज़ा दिलवाएँगे। कल इस मुद्दे पर रांची एसएसपी के साथ सरयू राय की बात हुई थी। परंतु सरयू राय का मानना है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है. इस मामले में पुलिस की भूमिका एक छात्रा के साथ व्यभिचार करने वालों को सजा दिलाने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए. इस मामले में पुलिस को जांच के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। गुरूवार को जारी प्रेस विज्ञाप्ति में विधायक सरयू राय ने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूचना मिली है कि रांची के जिस शैक्षणिक क्षेत्र में यह नृशंस घटना घटी है उस क्षेत्र में ऐसे कारनामे को अंजाम देने वाला एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जो छात्राओं को विविध प्रकार से फँसाता है और एक बार कोई लड़की फँस जाती है तो उसे चारा बनाकर यह गिरोह अन्य लड़कियों को फाँसता है। इस मामले में ओली विश्वकर्मा नामक जो लड़की ने जन्मदिन मनाने के बहाने पीड़िता को घटनास्थल पर ले गई थी वह भी इसी

प्रकार इस जालसाज़ गिरोह के चक्कर में फँसी थी और अब इस गिरोह के लिए काम कर रही है। ऐसी लड़कियों की बड़ी संख्या है जो इस गिरोह का शिकार बन चुकी हैं। यह गिरोह फोटो लेकर एवं वीडियो बनाकर लड़कियों को भयाक्रांत करता है. लोक लाज के डर से सहमी हुई लड़कियां, जिनमें ज़्यादातर छात्राएँ होती हैं, अपना मुँह बंद कर लेती हैं और यही इस गिरोह की सबसे बड़ी ताक़त है। अद्यतन मामले में पीड़िता छात्रा ने इस जघन्य दुष्कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया, बहादुरी के साथ प्रतिकार किया। नतीजा है कि दुष्कर्मी पुलिस के चंगुल में गिरफ़्तार हो गए हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक इन दुष्कर्मियों को कठोर सजा दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं पर इतना ही काफी नहीं है। न्याय का तक़ाज़ा है कि पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश करे, गिरोह के सरगना पर हाथ डाले। इस मामले को एक पीड़िता तक सीमित नहीं रखे। अब तक जितनी लड़कियां इस गिरोह का शिकार हो चुकी हैं उन सबको न्याय दिलाए। संभव है इस लक्ष्य के अनुरूप होने वाली पुलिसिया जांच में किसी राष्ट्रविरोधी षड्यंत्रकारी समूह के चेहरे पर से पर्दा उठे और इस क्रम में सफ़ेदपोशों का दबाव पुलिस जांच पर पड़े। इसके मद्दे नज़र सरकार गहन जांच के लिए या तो एसआईटी गठित करे या जांच को सीबीआई के हवाले कर दे।

न्यूज कॉर्नर

अर्जुन और आदित्य ने यूएस ओपन में एक और स्वर्ण पदक जीता

नयी दिल्ली: अर्जुन सिंह ने आदित्य सिंह की भारतीय जोड़ी ने फ्लोरिडा के नेपल्स में चल रही यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जे मेओडे और डब्ल्यू लिन को 9-11, 11-2, 11-7 से हराकर पुरुष युगल 5.0 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. भारत के ही पंथ ठक्कर और अथर्व शेठ की जोड़ी ने 4.5 पुरुष युगल वर्ग में रजत पदक जीता. उन्हें फाइनल में कैयन एप्पल और माइकल वैन ड्यूसेन से 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा. अर्जुन और आदित्य ने कहा, ''यूएस ओपन में एक और स्वर्ण पदक जीतना बेहद संतोषजनक है. हमने फिर से मिलकर यह खिताब जीता है जिससे यह और खास बन जाता है. हम आगे भी जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे.'' अर्जुन का यह टूर्नामेंट में तीसरा स्वर्ण पदक है. अपने भाई आदित्य के साथ उनका दूसरा स्वर्ण पदक है. इससे पहले टूर्नामेंट में उन्होंने लड़कों के अंडर-18 में युगल खिताब जीता था.

शुभंकर ने 64 का कार्ड खेला, बोल्डर्स क्लासिक खिताब जीतने के करीब

हैदराबाद: शीर्ष पर चल रहे शुभंकर शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां एक करोड़ पुरस्कार राशि के शुरूआती बोल्डर्स क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट के तीसरे दौर में आठ अंडर 64 का शानदार कार्ड खेलकर सात शॉट की विशाल बढ़त हासिल की. दो बार के डीपी वर्ल्ड टूर विजेता 29 वर्षीय शुभंकर (66, 66, 64) का कुल स्कोर 20 अंडर 196 हो गया है. उन्होंने तीसरे दौर में नौ बर्डी लगाई और महज एक बोगी की. दिल्ली के राशिद खान, चंडीगढ़ के अंगद चीमा और विशेष शर्मा 13 अंडर 203 के कुल स्कोर से संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं.

सीएसके के लिए बड़ा झटका, खलील चोट के कारण आईपीएल से बाहर

नयी दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के तेज गेंदबाज खलील अहमद कूल्हे में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर हो गए हैं जो अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी इस फ्रेंचाइजी टीम के लिए करारा झटका है. खलील ने सीएसके की तरफ से अभी तक सभी पांच मैच में हिस्सा लिया है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 14 अप्रैल को खेले गए मैच के दौरान अपने दाहिने कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी. उन्होंने अब तक सीएसके की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य सदस्य थे. आईपीएल के एक सूत्र ने बताया, ''यह ग्रेड दो की चोट है और इसे ठीक होने में कम से कम 10-12 सप्ताह का समय लगेगा.'' इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 11 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं. भारत की तरफ से उन्होंने अपना आखिरी मैच जुलाई 2024 में खेला था.

टखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज डेविड पेन

नयी दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद को बृहस्पतिवार को एक और झटका लगा जब इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेविड पेन टखने की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बचे हुए सत्र से बाहर हो गए. पेन (35 वर्ष) सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पहले दो मैच में खेले थे और उन्होंने दो विकेट झटके थे. सनराइजर्स हैदराबाद ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''डेविड पेन टखने की चोट के कारण बचे हुए टाटा आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं.'' फ्रेंचाइजी ने लिखा, ''उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं. '' 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद अभी दो जीत और तीन हार के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है. टीम इस सत्र में खिलाड़ियों की चोटों से प्रभावित हुई है. इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ब्रायडन कार्स सत्र की शुरुआत में हाथ में लगी चोट के कारण बाहर हो गए थे जिससे टीम ने उनकी जगह श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को शामिल किया था. नियमित कप्तान पैट कमिंस 'स्ट्रेस' चोट की वजह से अभी तक इस सत्र में नहीं खेल पाए हैं. अब हालांकि वह ठीक हो गए हैं और उनके इस महीने के अंत में मैदान पर लौटने की उम्मीद है.

फ्रेंच ओपन की इनामी राशि में 10 प्रतिशत का इजाफा, सात करोड़ डॉलर से अधिक हुई

पेरिस: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की इनामी राशि में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे कुल इनामी राशि छह करोड़ 17 लाख यूरो (सात करोड़ 21 लाख डॉलर) हो गई है. यह कुल राशि पिछले साल के मुकाबले 53 लाख यूरो अधिक है. प्रतियोगिता 24 मई को पश्चिमी पेरिस के रोलां गैरो में शुरू होगी. पुरुष और महिला एकल चैंपियन को 28 लाख यूरो और उप विजेता को 14 लाख यूरो मिलेंगे. सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को सात लाख 50 हजार यूरो और पहले दौरे में हारने वाले खिलाड़ियों को 87 हजार यूरो मिलेंगे. पुरुष और महिला युगल के विजेताओं को छह लाख यूरो और मिश्रित युगल की चैंपियन जोड़ी को एक लाख 22 हजार यूरो मिलेंगे. पिछले साल कार्लोस अल्कारेज ने पांच सेट के तक चले फाइनल में यानिक सिनर को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता था जबकि कोको गॉफ ने एरिना सबालेंका को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया था.

केकेआर पहली जीत के लिए बेताब, घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा गुजरात

मैच शुरू होने का समय: शाम 7.30 बजे

अहमदाबाद: लगातार खराब प्रदर्शन के कारण दबाव में चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शानदार फॉर्म में चल रही गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अपनी लय में लौटकर पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी. कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच अभिषेक नायर के नेतृत्व में केकेआर की स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आ रही है. उसे अब तक पांच मैच में से चार मैच में हार का सामना करना पड़ा है. हर्षित राणा और आकाश दीप के चोटिल होने तथा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किए जाने के बाद टूर्नामेंट से पहले उसकी गेंदबाजी काफी कमजोर हो गई थी. उसके लिए हालांकि सबसे बड़ी चिंता सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन गेंदबाजों की खराब फॉर्म है. चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं. केकेआर की समस्याएं मैदान के अंदर और बाहर के कुछ फैसलों के कारण बढ़ गई हैं. टिम सीफर्ट और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखने पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि टॉस जीतने के बाद उसके फैसले भी समझ से परे हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द कर दिए गए मैच में रहाणे ने बल्लेबाजी का फैसला करके सभी को चौंका दिया, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने ऐसी पिच पर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो गेंदबाजों के अनुकूल थी. मुंबई इंडियंस के खिलाफ वह 220 रन के स्कोर का बचाव नहीं कर सकी जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 65 रन की हार ने उसकी समस्याएं और बढ़ा दी. इस तरह से केकेआर दिशाहीन टीम नजर आ रही है. अभी तक सारा ध्यान कैमरन ग्रीन पर रहा है जिन्हें आंद्रे रसेल की जगह भरने के लिए रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. ऑस्ट्रेलिया का यह ऑलराउंडर उस कीमत को सही ठहराने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन वह पांच पारियों में केवल 56 रन ही बना पाए हैं और गेंदबाजी में भी खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. केकेआर के बल्लेबाजी क्रम में भी स्पष्टता नजर नहीं आती. पिछले मैच में सुनील नारायण को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया जबकि रहाणे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे लेकिन यह दोनों ही बदलाव कारगर साबित नहीं हुए. मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी और सार्थक रंजन जैसे भारतीय बल्लेबाजों को अभी तक मौका नहीं मिला है. केकेआर को जीत हासिल करने के लिए अपनी रणनीति को बदलना होगा और तीनों विभाग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. गुजरात टाइटन्स की टीम भी अभी तक अपने घरेलू मैदान पर जीत हासिल नहीं कर पाई है. उसे अभी तक यहां खेले गए एकमात्र मैच में राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद उसने विरोधी टीम के मैदानों पर दो जीत हासिल की. उसकी गेंदबाजी मजबूत नजर आ रही है जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और राशिद खान ने अपनी लय वापस हासिल कर ली है. शुभमन गिल और जोस बटलर जैसे बल्लेबाजों के फॉर्म में आने से गुजरात टाइटन्स मजबूत नजर आ रहा है.

टीम इस प्रकार हैं : (गुजरात टाइटंस) : शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, आर साई किशोर, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, जयंत यादव, कुलवंत खेजरोलिया. **(कोलकाता नाइट राइडर्स)** : अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, फिन एलन, दक्ष कामरा, कार्तिक त्यागी, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे.

गेंदबाज पंत को आउट नहीं कर रहे, अधिकतर वह खुद आउट हो रहा है: सिद्धू

नयी दिल्ली: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऋषभ पंत अपनी विकेट खुद ही गंवा रहे हैं जबकि वह इसके लिए गेंदबाजों को मेहनत नहीं करवा रहे और इसी वजह से मौजूदा आईपीएल सत्र में लखनऊ सुपर जाइंट्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. मौजूदा सत्र में पंत का प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है जिसमें कई बार उन्होंने बहुत कम स्कोर बनाए हैं. उन्होंने एकमात्र अच्छी पारी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 68 रन की खेली. सुपर जाइंट्स की टीम इस समय अंक तालिका में सातवें स्थान पर है जिसकी मुख्य वजह उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना है. पंत और सुपरजाइंट्स के बारे में बात करते हुए सिद्धू ने कहा, ''उन्हें अपनी कमियों पर काफी गहराई से सोचने की जरूरत है. उनकी समस्याएं बनी हुई हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि उनका शीर्ष क्रम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है. वे अपने शुरुआती तीन बल्लेबाजों पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला है.'' उन्होंने कहा, ''जब आप (एडेन) मारक्रम, (निकोलस) पूरन, (मिचेल) मार्श और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं तो उनमें जबरदस्त क्षमता नजर आती है लेकिन उनके बीच साझेदारी की कमी है.'' सिद्धू ने कहा, ''शीर्ष क्रम में 50 रन की साझेदारी भी बहुत कम देखने को मिली है. मुझे नहीं लगता कि गेंदबाज ऋषभ को आउट कर रहे हैं बल्कि अधिकतर वह खुद ही आउट हो रहे हैं. उनमें प्रतिभा और क्षमता दोनों हैं और अगर वह खुद को थोड़ा समय दे तो वह अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं. फिलहाल उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही संघर्ष करती नजर आ रही हैं.'' बुधवार को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पांच विकेट की हार के दौरान पंत सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे. पंत लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पांच मैच में सिर्फ 104 रन बना पाए हैं. उनका औसत 26.00 और स्ट्राइक रेट 122.35 का है. सिद्धू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विराट कोहली की रनों की भूख से काफी प्रभावित हुए जबकि वह लगभग दो दशकों से शीर्ष स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हैं. सिद्धू ने कहा, ''विराट कोहली अगर अपनी 20 प्रतिशत क्षमता से भी खेले तो भी वह अधिकतर खिलाड़ियों के शत प्रतिशत प्रदर्शन से बेहतर होते हैं. उनका प्रभाव और दबदबा ही कुछ ऐसा है. शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद उन्होंने जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली.'' सिद्धू ने कहा, ''जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद शमी पर दबदबा बनाया वह देखने लायक था. वह अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से शॉट लगा रहे थे और बहुत ही सहजता से पुल और कट शॉट खेल रहे थे.''

बरवाल की नजरें अब एशियाई खेलों के मैराथन पदक पर

नयी दिल्ली: हाल में भारतीय एथलेटिक्स का सबसे पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मैराथन धावक सावन बरवाल का लक्ष्य एशियाई खेलों में देश के लिए 1982 के बाद इस दूरी का पहला पदक जीतना है. मैराथन में भारत का आखिरी एशियाई खेल पदक होसुर कुक्कप्पा सीतारण ने 1982 में नयी दिल्ली में जीता था. उससे पहले छोटा सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में हुए शुरूआती 1951 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. महान एथलीट शिवनाथ सिंह ने 48 साल तक 2:12:00 का राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड अपने नाम किया था. लेकिन 28 साल के बरवाल ने रविवार को एनएन रॉटरडैम मैराथन में उस लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 2:11:58 के नए समय के साथ 20वें स्थान पर रहे. बरवाल ने पीटीआई से कहा, ''इस साल मेरा मुख्य लक्ष्य एशियाई खेल होंगे और मैं वहां पदक जीतना चाहता हूं. मैं बहुत ज्यादा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लूंगा.'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि मैं अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड और बेहतर कर सकता हूं. अगर ठंडी हवा नहीं होती तो मैं रॉटरडैम में भी लगभग 2:10:00 में दौड़ सकता था. इसलिए मैं अपने अभी के राष्ट्रीय रिकॉर्ड से भी तेज दौड़ सकता हूं.'' बरवाल ने कहा, ''अगले साल एशियाई मैराथन चैंपियनशिप है. फिर मैं 2028 ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहूंगा.'' बरवाल की अगले महीने शादी हो रही है. उन्होंने अपनी पहली रेस में ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें यह कामयाबी हासिल करने का भरोसा था क्योंकि वह जनवरी से ही रेस की तैयारी कर रहे थे. उन्हें पिछले साल दिसंबर में वालेंसिया मैराथन में दौड़ना था, लेकिन चोट लगने की वजह से वह इसमें हिस्सा नहीं ले पाए. बरवाल ने कहा, ''मैं कुन्नूर में ऊंचाई के क्षेत्र में ट्रेनिंग कर रहा था और मैं अच्छी तैयारी कर रहा था. मुझे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने का भरोसा था.'' उन्होंने कहा, ''लक्ष्य 2:10:00 के समय का था और 40 किमी तक सब कुछ योजना के मुताबिक ही हुआ. आखिरी दो किलोमीटर में दिक्कतें आईं. मुझे ठंडी हवा का अंदाजा नहीं था और ऊपर से मैंने अपने शरीर पर पानी भी डाला था.''

एमसीए ने 2026-2027 सत्र से पहले खिलाड़ियों के लिए अनुबंध प्रणाली की घोषणा की

मुंबई: मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने 2026-2027 सत्र से पहले अपनी संस्था को पेशेवर बनाने के लिए बृहस्पतिवार को खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली की घोषणा की. इस तरह वह इस तरह की व्यवस्था शुरू करने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ बन गया है. ग्रेड ए के खिलाड़ियों को हर साल 12 लाख से 20 लाख रुपये जबकि ग्रेड बी के खिलाड़ियों को आठ लाख से 12 लाख रुपये दिए जाएंगे. ग्रेड सी में रखे जाने वाले खिलाड़ियों को हर साल आठ लाख दिए जाएंगे. एमसीए ने एक बयान में कहा, ''यह पहल उभरते हुए क्रिकेटरों को वित्तीय सुरक्षा और पेशेवर ढांचा प्रदान करेगी जो लंबे समय के विकास के रास्ते पर एक नए युग की शुरुआत करेगी.'' खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन, फिटनेस मानकों और चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुबंध दिए जाएंगे. मुंबई के अनुबंधित खिलाड़ियों को बोर्ड की नीति के मुताबिक मैच फीस, दैनिक भत्ते और प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा, ''यह पहल मुंबई क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है. हमें खिलाड़ियों की अनुबंध प्रणाली लागू करने वाला पहला संघ होने पर गर्व है.''

दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए शानदार मौका : हरमनप्रीत कौर

डरबन: भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टी20 विश्व कप से पहले सभी खिलाड़ियों को उचित मौका दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी टीम आत्मविश्वास से भरी है और शुक्रवार से यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. हरमनप्रीत ने यह भी कहा कि वनडे विश्व कप जीतने के बाद उनकी टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. भारत ने हाल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं में जीत दर्ज की है. भारतीय कप्तान ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले इंग्लैंड एवं वेल्स में 12 जून से पांच जुलाई तक होने वाले वैश्विक टूर्नामेंट से पहले उन्हें संयोजन को परखने और लय बनाने का मौका देंगे. हरमनप्रीत ने श्रृंखला से पहले आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''हम इस मौके को बहुत गंभीरता से लेना चाहते हैं और यहां अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना चाहते हैं. विश्व कप से पहले यह हमारे लिए एकजुट होने और अच्छी तैयारी का शानदार मौका है.'' भारत ग्रुप ए में आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के साथ है. हरमनप्रीत ने कहा कि पांच मैच की श्रृंखला में सभी खिलाड़ियों को मौका देना ही प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा, ''ये मैच यह सनुश्चित करने के लिए काफी अहम हैं कि सभी खिलाड़ियों को बराबर मौके मिले ताकि हम विश्व कप के लिए जाने से पहले एक इकाई की तरह पूरी तरह तैयार रहें. साथ ही हम यहां जीत दर्ज करना चाहेंगे.'' उन्होंने कहा, ''वनडे विश्व कप के बाद टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. टीम अच्छी लय में हैं और विश्व कप से पहले हमारे लिए यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है.''

परिस्थितियों के बारे बात करते हुए हरमनप्रीत ने कहा, ''यहां का मौसम बिलकुल भारत की तरह है. अंतर सिर्फ पिच में है, लेकिन हम इसके आदि हो रह हैं और उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे.'' टीम संयोजन पर उन्होंने संकेत दिया कि यह दक्षिण अफ्रीका के हालात को देखकर किया जाएगा, विशेषकर तेज गेंदबाजों के कई विकल्प की जरूरत को देखते हुए. उन्होंने साथ ही अनुभवी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की अगुआई वाले स्पिन आक्रमण पर भी पूरा भरोसा दिखाया.

आईडब्ल्यूएल का दूसरा चरण 27 अप्रैल से कोलकाता में

कोलकाता: इंडियन वुमेंस लीग (आईडब्ल्यूएल) 2025-26 के दूसरे चरण की शुरुआत यहां 27 अप्रैल को ईस्ट बंगाल एफसी और श्रीभूमि एफसी के बीच मुकाबले के साथ होगी. यह पहले चरण का मुकाबला है जिसके कार्यक्रम में बदलाव किया गया था. पहला चरण का आयोजन 20 दिसंबर 2025 से नौ जनवरी 2026 तक किया गया जिसमें जिसमें 27 मैच खेले गए थे. लीग ने तीन महीने से अधिक का ब्रेक लिया था जिससे कि खिलाड़ी सीनियर और अंडर-20 महिला राष्ट्रीय टीम के शिविर के लिए उपलब्ध हो सकें और मार्च में एएफसी महिला एशियाई कप तथा अप्रैल में एएफसी अंडर-20 महिला एशियाई कप में हिस्सा ले सकें. दूसरे चरण में 27 अप्रैल से 18 मई तक 29 और मैच खेले जाएंगे. इसमें आठों टीम लीग के डबल राउंड रोबिन प्रारूप के दूसरे चरण में एक-दूसरे से खेलेंगी. ये मैच दो स्थलों एआईएफएफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ईस्ट बंगाल ग्राउंड में खेले जाएंगे. सभी मैच दोपहर तीन बजे और शाम सात बजे से शुरू होंगे. मौजूदा चैंपियन ईस्ट बंगाल एफसी फिलहाल छह मैच में 18 अंक के साथ तालिका में सबसे ऊपर है जबकि सेसा एफए और किकस्टार्ट एफसी क्रमशः एक और छह अंक के साथ रेलीगेशन (निचली लीग में खिचकना) का खतरा झेल रहे हैं.

कच्चे तेल में तेजी के बावजूद 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी: एसएंडपी

नयी दिल्ली: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच यदि चालू वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल रहती है, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है. इसमें यह भी कहा गया कि ऊर्जा की कीमतों के झटके से होने वाले राजकोषीय दबाव का भारत की संप्रभु साख रेटिंग पर असर पड़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि भारत के पास लंबी अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राजनीतिक प्रतिबद्धता है. एसएंडपी के निदेशक (संप्रभु एवं अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंग) यी फर्न फुआ ने कहा कि अगर कच्चे तेल की औसत कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल रहती है तो भारत 2026-27 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा. फुआ ने एक वेब गोष्ठी में कहा, दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में यह आंकड़ा अभी भी बहुत मजबूत है. वैकल्पिक परिदृश्य में भी, अगर मैं कहूं कि औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल रहती है, तो भी हम 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर देख रहे हैं. ऐसे में भी भारत की वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी. एसएंडपी ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान, जिससे ईंधन या उर्वरक जैसे संबंधित उत्पादों की कमी होती है, एक जोखिम होगा.

मजबूत वैश्विक संकेतों से चांदी 1,700 रुपये चढ़ी, सोना टूटा

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 1,700 रुपये बढ़कर 2.58 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. इसकी वजह लगातार मांग और मज़बूत वैश्विक रुख था, जबकि निवेशक भू-राजनीतिक घटनाक्रम और मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर नज़र रखे हुए थे. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 1,700 रुपये या लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 2,58,700 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई, जबकि पिछली सत्र में यह 2,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. हालांकि, 99.9 प्रतिशत वाला सोना 200 रुपये टूटकर 1,57,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गया. बुधवार को, सोने की कीमत 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ''बृहस्पतिवार को सोने में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, जो मिले-जुले बाजार संकेतों को दिखाता है. होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास चल रही अस्थिरता ने डॉलर की सुरक्षित निवेश मांग को समर्थन दिया, जिसने कीमती धातु के लिए एक बड़ी रुकावट का काम किया.'' उन्होंने कहा कि डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में सुधार ने कीमती धातु में बढ़त को और कम कर दिया. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच नए राजनयिक जुड़ाव की उम्मीदों से कुल जोखिम धारणा में सुधार हुआ.

कारोबार

वित्तीय कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली से सेंसेक्स 123 अंक टूटा, निफ्टी 24,200 अंक के नीचे

मुंबई: उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 123 अंक टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी 24,200 अंक के नीचे बंद हुआ. हाल की तेजी के बाद बैंक और वित्तीय शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार नुकसान में रहा. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरुआती बढ़त को गंवाते हुए 122.56 अंक यानी 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,988.68 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और 78,730.32 अंक तक पहुंच गया. हालांकि, बाद में ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली से यह गिरावट के साथ 77,674.93 अंक के निचले स्तर पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 1,055.39 अंक का उतार-चढ़ाव आया. एनएसई निफ्टी भी 34.55 अंक यानी 0.14 प्रतिशत टूटकर 24,196.75 अंक पर बंद हुआ. सूचकांक ऊंचे में 24,400.95 तक गया और नीचे में 24,102.80 अंक तक आया. पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेत के बीच दोनों मानक सूचकांकों में बुधवार को एक प्रतिशत से अधिक की तेजी आई थी. सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा 1.75 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके अलावा टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस में प्रमुख रूप से गिरावट दर्ज की गई. दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में ट्रेंट, इटर्नल, अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फोसिस शामिल हैं. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''घरेलू बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही. हालांकि, उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सौदों की साप्ताहिक समाप्ति के दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. निवेशकों ने हाल की बढ़त के बाद मुनाफावसूली की. बाजार को अमेरिका-ईरान वार्ता के दूसरे दौर पर स्पष्टता का इंतजार है, जो निकट भविष्य के बाजार के रुख को दिशा देगा.'' मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.86 प्रतिशत चढ़ा जबकि छोटी कंपनियों से जुड़ा स्मॉलकैप सेलेक्ट 0.60 प्रतिशत के लाभ में रहा. लाइवलॉन्ग वेल्थ के शोध विश्लेषक और संस्थापक हरिप्रसाद के ने कहा, ''भारतीय बाजार में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला. यह हाल की तेजी के बाद सुधार की ओर बदलाव को दर्शाता है. बेहतर वैश्विक संकेतों और भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी के कारण सूचकांक सकारात्मक शुरुआत के साथ खुला, लेकिन बाद में मुनाफावसूली के कारण उच्च स्तर को बनाए रखने में विफल रहा.'' उन्होंने कहा कि वृहद परिप्रेक्ष्य से, पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों के प्रति बाजार धारणा संवेदनशील बनी हुई है. क्षेत्रवार रुझान मिलाजुला रहा. धातु, आईटी और ऊर्जा शेयरों ने सूचकांक को सहारा दिया, जबकि बैंक और वाहन शेयरों पर कुछ दबाव देखने को मिला. एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोप के बाजार दोपहर के कारोबार में सकारात्मक दायरे में थे. अमेरिकी बाजार बुधवार को ज्यादातर बढ़त के साथ बंद हुए थे. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.51 प्रतिशत बढ़कर 96.36 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 666.15 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. सेंसेक्स बुधवार को 1,263.67 अंक बढ़कर 78,111.24 अंक पर बंद हुआ था. निफ्टी 388.65 अंक बढ़कर 24,231.30 अंक पर रहा था.

पश्चिम एशिया में मांग पर असर नहीं, अशोक लेलैंड ने पेश किए दो ईंधन वाले एलसीवी मॉडल

नयी दिल्ली: वाणिज्यिक वाहन कंपनी अशोक लेलैंड ने पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद मांग मजबूत बनी होने का जिक्र करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित उसके संयंत्र के उत्पादन पर असर पड़ा है. कंपनी के अध्यक्ष (हल्के वाणिज्यिक वाहन, अंतरराष्ट्रीय परिचालन, रक्षा एवं बिजली समाधान) अमनदीप सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा हालात का वित्त वर्ष 2026-27 के प्रदर्शन पर संभावित असर का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन भारत में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के कारण लॉजिस्टिक और कलपुर्जों की आपूर्ति में कुछ बाधाएं आई हैं, जिससे मार्च में उत्पादन थोड़ा घट गया. उन्होंने कहा, हम वैकल्पिक मार्ग और लॉजिस्टिक व्यवस्था पर काम कर रहे हैं ताकि संयंत्र का संचालन सामान्य हो सके. स्थिति जल्द सुधरने की उम्मीद है. इसके साथ ही सिंह ने कहा कि ईरान से जुड़े तनाव इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की मांग को बढ़ावा दे सकते हैं और कंपनी इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है. सिंह ने कहा, ''कंपनी के हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) मॉडल 'दोस्त' और 'बड़ा दोस्त' पहले से ही इलेक्ट्रिक संस्करण में उपलब्ध हैं और उनकी अच्छी संख्या में बिक्री हो रही है.'' इसी क्रम में अशोक लेलैंड ने बृहस्पतिवार को 'दोस्त' और 'दोस्त प्लस एक्सएल' के दोहरे ईंधन (सीएनजी और पेट्रोल) वाले संस्करण भी पेश किए. इन संस्करणों में ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से दोनों ईंधन के बीच 'स्विच' कर सकते हैं. सिंह ने कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद खाड़ी देशों में मांग में कोई कमी नहीं आई है और ऑर्डर रद्द होने के मामले भी नहीं देखे गए हैं.

रुपया 10 पैसे की बढ़त के साथ 93.23 प्रति डॉलर पर

मुंबई: पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम की उम्मीदों के बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 93.23 (अस्थायी) पर रहा. विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी ने स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने से घरेलू मुद्रा में तेजी आई. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 93.29 पर खुला और दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले 93.16 के ऊपरी और 93.35 के निचले स्तर तक गया. कारोबार के अंत में यह 93.23 (अस्थायी) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त है. रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे बढ़कर 93.33 पर बंद हुआ था. एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक (जिंस एवं मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि रुपये की बढ़त मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों से प्रेरित है. इस वजह से पिछले 48 घंटों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और इससे भारत के आयात बिल पर दबाव कम हुआ है. त्रिवेदी ने कहा, ''हालांकि, यह सुधार नाजुक बना हुआ है, क्योंकि बाजार की भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर है और कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तरह की तेजी का असर रुपये पर तुरंत पड़ सकता है. रुपये का दायरा 92.75-93.75 के बीच रह सकता है.''

न्यूज कॉर्नर

विदेशी लिंक वाले साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया के जरिये विदेशी लोगों के संपर्क में रहकर ठगी कर रहा था. इस मामले में पुलिस ने एक बैंक कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरेली निवासी एक व्यक्ति के खाते से फरवरी में 10,000 रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर की गयी शिकायत के बाद यह मामला सामने आया. पुलिस ने जांच के दौरान मयूर विहार फेज-1 स्थित एक निजी बैंक शाखा में एक संदिग्ध खाते की पहचान की, जिसमें ऐसी ही कई शिकायतें संबद्ध थीं. बाद की जांच में पता चला कि एक फर्म के नाम पर खोला गया खाता, साइबर धोखाधड़ी लेनदेन के लिए बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, खाता धारक शौकीन और उसके सहयोगी शाहरुख उर्फ जोजो को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान जोजो ने एक बैंक रिलेशनशिप मैनेजर की संलिप्तता का खुलासा किया, जिसने आर्थिक लाभ के लिए म्यूल खाते खोलने में मदद की.

सीबीएसई परिणाम में मिले अंकों से निराश 10वीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या

गुरुग्राम: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद यहां एक छात्र ने अपने घर पर कथित रूप से आत्महत्या कर ली. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पुलिस को संदेह है कि 16 वर्षीय कुणाल ने अपनी उम्मीदों पर खरा न उतरने से निराश होकर यह कदम उठाया होगा. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ऐसा संदेह है कि छात्र ने अपना परिणाम देखने और उम्मीद के मुताबिक अंक न मिलने के बाद यह कदम उठाया. पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार शाम को पटौदी थाना क्षेत्र के जटौली इलाके में बाबा हरदेव कॉलोनी में हुई. परिवार के सदस्यों ने बताया कि कुणाल ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आने से वह निराश था. पुलिस ने बताया कि कुणाल के माता-पिता ने उसे दोबारा परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया, लेकिन वह अवसाद में रहने लगा. पुलिस के मुताबिक, परिणाम घोषित होने के बाद कुणाल छत पर बने एक कमरे में चला गया जबकि परिवार के अन्य सदस्य घटना के समय घर के दूसरे कमरे में थे. पुलिस ने बताया कि बाद में जब परिवार के सदस्य ऊपर गए तो उन्होंने कमरा अंदर से बंद पाया और दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर कुणाल का शव फंदे से लटका हुआ मिला.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. याचिका में इन प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण हैं. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की ओर से मामले में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण द्वारा दी गई दलीलों पर गौर किया और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया. याचिका में कहा गया है कि वर्तमान शरीयत उत्तराधिकार नियम महिलाओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण हैं. भूषण ने कहा कि 1937 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार से जुड़े मामले दीवानी प्रकृति के होते हैं और ये अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं हैं. वकील ने कहा, यह कहना कि महिलाओं को पुरुष समकक्षों की तुलना में आधा या उससे भी कम मिलेगा, भेदभावपूर्ण है.

हत्या मामले में कांग्रेस विधायक कुलकर्णी व अन्य के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित

बेंगलुरु: कर्नाटक में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने 2016 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 16 अन्य लोगों की सजा की अवधि पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस संबंध में फैसला 17 अप्रैल को सुनाया जाएगा. अदालत ने बुधवार को आरोपियों को आपराधिक साजिश और संबंधित अपराधों का दोषी ठहराया था. अदालत ने गुरुवार को सजा की अवधि पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं. न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने अभियुक्तों को योगेश गौड़ा की हत्या के लिए आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया और उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) सहित संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.

चींटियों की तस्करी में चीनी व्यक्ति को एक वर्ष के कारावास की सजा

नैरोबी (केन्या): केन्या की एक अदालत ने चींटियों की तस्करी करने का दोषी पाए जाने पर एक चीनी नागरिक को बुधवार को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. चीनी नागरिक कई विशेष ट्यूब में चींटियों की कथित तौर पर तस्करी कर रहा था. बिना लाइसेंस के वन्यजीवों को कब्जे में रखने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद झांग केकुन पर दस लाख केन्याई शिलिंग (7,700 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया गया. केन्या ने पहले भी बेल्जियम के किशोरों पर जुर्माना लगाया था, जिनके कब्जे में रानी चींटियां पाई गयी थी. इन चींटियों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है और यूरोप तथा एशिया में इन्हें पालतू के रूप में भी रखा जाता है. केकुन के साथ इस मामले में केन्याई नागरिक चार्ल्स म्वांगी को भी आरोपी बनाया गया था जिसने आरोप स्वीकार नहीं किए और उसे नकद जमानत पर रिहा कर दिया गया. अभियोजकों के अनुसार, केकुन कथित तौर पर म्वांगी से चींटियां हासिल कर रहा था और उसने शुरुआती 600 चींटियों के लिए 60,000 केन्याई शिलिंग (463 अमेरिकी डॉलर) तथा 700 चींटियों की एक अन्य खेप के लिए 70,000 शिलिंग (540 अमेरिकी डॉलर) का भुगतान किया था. अधिकारियों द्वारा 10 मार्च को संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से विशेष ट्यूबों में रखी 1,948 गार्डन चींटियां और टिशू रोल में रखी अतिरिक्त 300 चींटियां बरामद की गईं.

जनगणना जातियों की गिनती के साथ हो रही है, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक: अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है और जातियों के साथ ही यह जनगणना होगी. उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण गैर-संवैधानिक है. लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किये जाते समय समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव की कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए शाह ने ये बातें कहीं.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में आज संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया. विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से जिस तरह परिसीमन को जनगणना से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, वह संविधान की भावना के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक में पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए.

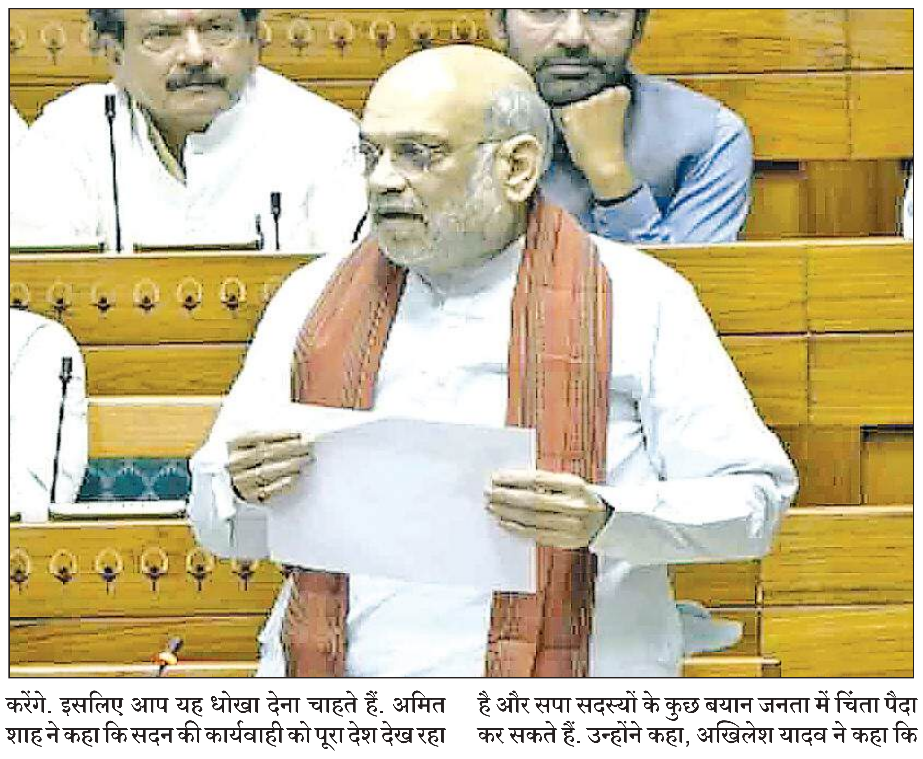

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार को विधेयक लाने की इतनी जल्दीबाजी क्या है? उन्होंने कहा, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? जैसे ही जनगणना होगी, हम जातीय जनगणना की मांग करेंगे, जातीय जनगणना होगी तो हम आरक्षण की मांग करेंगे. इसलिए आप यह धोखा देना चाहते हैं. अमित शाह ने कहा कि सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है और सपा सदस्यों के कुछ बयान जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं. उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है? मैं बताना चाहता हूं कि देश में जनगणना शुरू हो चुकी है और जारी है. शाह ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने जातीय जनगणना की बात कही तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जातियों की जनगणना का निर्णय पहले ही ले चुकी है और जाति के साथ ही यह जनगणना हो रही है.

जनगणना में जातियों का कॉलम नहीं होने संबंधी धर्मेंद्र यादव के आरोप पर शाह ने कहा, जनगणना में अभी घरों की गिनती हो रही है. घरों की कोई जाति नहीं होती. सपा का वश चले तो घरों की भी जाति तय कर दे. जब घरों की गिनती के बाद नागरिकों की जनगणना होगी, उसमें जाति का कॉलम होगा. उन्होंने कहा, धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम आरक्षण की गैर-संवैधानिक बात कही. है. संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देता. मैं सरकार का संकल्प दोहराता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों का आरक्षण गैर संवैधानिक है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने भी धर्मेंद्र यादव के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है और सदस्य को इस तरह की असंवैधानिक बात नहीं बोलनी चाहिए. उन्होंने कहा, हम पूरे देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं. आप केवल मुस्लिम महिलाओं की बात क्यों कर रहे हैं? यह राजनीतिक बयान है. शाह ने यह भी कहा, सपा चाहे तो सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है.

भ्रष्टाचार के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतने की नीति अपना रही सरकार: मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतने की नीति अपना रही है और नागरिकों के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है. शर्मा ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवधि में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है.

उन्होंने कहा कि हत्या के मामलों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26 प्रतिशत और लूटपाट में 50.75 प्रतिशत की कमी आई है जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका अहम है और उनके प्रयासों से लोगों में सुरक्षा की भावना बनी है. उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है. शर्मा ने बताया कि

हाल ही में स्वापक रोधी कार्य बल, विशेष थाना और कई चौकियां स्थापित की गई हैं. उन्होंने कहा, साथ ही गैंगस्टर रोधी कार्य बल संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है. थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती की गई है और नई इकाइयां व थाने बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्रदान किए और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी नया पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया.-

सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 महिलाओं से दो करोड़ रुपये ठगे, गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल के जरिए डॉक्टर, फिल्म निर्माता, वकील, कारोबारी एवं मॉडल बनकर देशभर की 500 से ज्यादा महिलाओं से दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में 35 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है. दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमित गोयल ने एक बयान में बताया कि जिले की साइबर पुलिस की एक टीम ने आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसपर डेटिंग और विवाह संबंधी मंचों के माध्यम से महिलाओं को निशाना बनाकर 'रोमांस स्कैम', मोहपाश और ऑनलाइन ब्लैकमेल का एक संगठित नेटवर्क चलाने के आरोप हैं. पुलिस ने बताया कि कुमार महिलाओं से संपर्क करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के साथ-साथ डेटिंग और विवाह संबंधी ऐप पर फर्जी पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाता था. डीसीपी ने कहा, वह खुद को एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले सुस्थापित पेशेवर व्यक्ति के रूप में पेश करता था, और भरोसा जीतने और पीड़िताओं को आकर्षित करने के लिए अक्सर

खुद को डॉक्टर, व्यवसायी या फिल्म निर्माता बताता था. जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी पीड़िताओं से दोस्त के तौर पर बातचीत शुरू करता था और धीरे-धीरे कई दिनों या हफ्तों में उनके साथ भावनात्मक संबंध बनाता था और विश्वास कायम होने के बाद, वह उनके साथ निजी मैसेजिंग मंचों पर जाकर बातचीत करता था और इन मंचों का इस्तेमाल कई मोबाइल नंबरों के जरिए किया जाता था ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके. उन्होंने कहा, आरोपी ने एक ही समय में कई पीड़ितओं से समानांतर बातचीत की. उसने भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया और पीड़िताओं को अपने भरोसे में लेने के लिए घनिष्ठता का भाव पैदा किया.

अधिकारी ने बताया कि पीड़िताओं का विश्वास जीतने के बाद, कुमार उनसे पैसे ऐंठने के लिए चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति, कारोबार में घाटा, पारिवारिक संकट या आर्थिक तंगी जैसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता था. कई मामलों में, वह पीड़िताओं को लुभाने के लिए शादी या मॉडलिंग असाइनमेंट या प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाने जैसे आकर्षक अवसरों का भी वादा करता था. डीसीपी ने कहा कि एक मामले में, 'वैभव अरोड़ा' नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसने एक महिला से कथित तौर पर लगभग सात लाख रुपये ऐंठ लिए.

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने पहले एक डेटिंग ऐप पर इस महिला से दोस्ती की और बाद में शादी का वादा किया. आरोपी ने एक और फर्जी पहचान के आधार पर आईडी बनाई और इसमें खुद को कुमार का दोस्त बताते हुए महिला से परिचय किया और दावा किया कि वह उनके रिश्ते को औपचारिक रूप में तय करने में मदद करेगा.

यूक्रेन में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत

कीव: रूस ने यूक्रेन के नागरिक क्षेत्रों पर कई घंटे तक सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया. इस हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए और 80 से अधिक लोग घायल हो गए. लगभग दो सप्ताह में यूक्रेन को निशाना बनाकर किया गया रूस का यह सबसे बड़ा हवाई हमला था. अधिकारियों ने बताया कि रूस ने लगभग 700 ड्रोन और कई बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलें दागीं, जिनका मुख्य निशाना आम नागरिक थे. रूस ने चार साल से अधिक समय पहले पड़ोसी देश पर आक्रमण किया था और तब से रूसी सेना लगभग हर दिन नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रही है. नियमित हमलों के बीच-बीच में बड़े पैमाने पर हमले भी होते रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इन हमलों में 15,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं.

ताजा बमबारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की इस सप्ताह जर्मनी, नॉर्वे और इटली की 48 घंटे की

यात्रा के बाद हुई है. यात्रा के दौरान जेलेंस्की ने रूसी मिसाइलों को रोकने में सक्षम और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की तत्काल मांग की थी. यूक्रेन को डर है कि ईरान युद्ध के कारण उन उन्नत अमेरिका-निर्मित प्रणालियों के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिनकी उसे आवश्यकता है. साथ ही, उसने रूसी तेल पर अमेरिकी अस्थायी छूट का विरोध किया है. यूक्रेन का कहना है कि इससे रूस के युद्ध प्रयासों को वित्तीय मदद मिल रही है.

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर कहा, इस तरह के हमलों को सामान्य नहीं माना जा सकता. ये युद्ध अपराध हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए और इनके दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. सिबिहा ने बताया कि कीव में कम से कम चार लोग मारे गए, जिनमें 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं. दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा में नौ लोग मारे गए और 23 अन्य घायल हो गए जबकि मध्य नीप्रो क्षेत्र में तीन लोग मारे गए और लगभग 36 व्यक्ति घायल हो गए और दक्षिण में जापोरिजिया में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि हवाई सुरक्षा बलों ने 703 लक्ष्यों में से 667 को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया, जिनमें 636 शाहेद-किस्म के ड्रोन और अन्य ड्रोन शामिल थे. वायु सेना ने बताया कि 20 स्ट्राइक ड्रोन और 12 मिसाइलों ने 26 स्थानों को निशाना बनाया.

पंजाब: आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से चार हथगोले बरामद किए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर व मोहाली के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठों और पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग के संयुक्त अभियान में दो विदेशी पिस्तौल और गोला-बारूद भी बरामद किए गए. यादव ने एक पोस्ट में बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहा था और चंडीगढ़ में हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले में शामिल आतंकी मॉड्यूल से उसके संबंध हैं. पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अमृतसर के 'पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल' में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच जारी है.

राज्यसभा चुनाव में 'क्रॉस-वोटिंग' के लिए कांग्रेस ने पांच विधायकों को किया निलंबित

चंडीगढ़: हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों को पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर 'क्रॉस-वोटिंग' करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन का गंभीर संज्ञान लेते हुए, पार्टी ने पांच विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य अनुशासन समिति की सिफारिश और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद यह कार्रवाई की गई है. नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, साढौरा विधायक रेणु बाला, पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन सीट से विधायक मोहम्मद इसराइल और रतिया से विधायक जरनैल सिंह पर पार्टी की

आधिकारिक लाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति (डीएसी) ने हाल में पांच विधायकों के निलंबन की सिफारिश की थी. समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने पूर्व में कहा था कि समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में पांच पार्टी विधायकों द्वारा कथित 'क्रॉस-वोटिंग' के मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व को अपना निर्णय बता दिया है.

चुनावों में मतदान को अनिवार्य बनाने संबंधी जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देश में मतदान को अनिवार्य बनाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा फैसला ''नीतिगत क्षेत्र'' में आता है और न्यायपालिका इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकती. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित पक्षों के समक्ष रखें.

पीठ ने कहा कि जानबूझकर मतदान न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान लागू करने और मतदान को अनिवार्य बनाने जैसी मांगों पर अदालत विचार नहीं कर सकती. याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि जो लोग जानबूझकर मतदान नहीं करते, उनके लिए सरकारी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएं. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र कानूनी दबाव से नहीं, बल्कि जन-जागरूकता से फूलता-फलता है. उन्होंने कहा, एक ऐसे देश में, जो कानून के

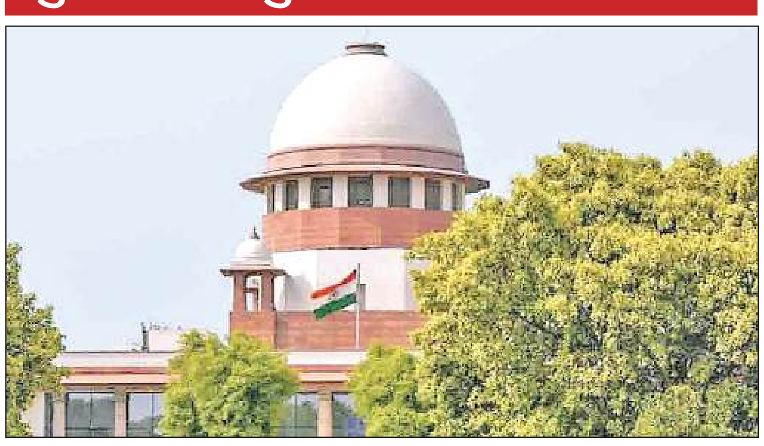

शासन पर चलता है और लोकतंत्र में विश्वास करता है और जहां हमने 75 वर्षों में इस पर भरोसा दिखाया है, हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह मतदान करने जाए. अगर वे नहीं जाते, तो नहीं जाते. जरूरत जागरूकता की है, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते. याचिकाकर्ता ने भी सुझाव दिया कि अदालत निर्वाचन आयोग को गैर-मतदाताओं के लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने का निर्देश दे. इस पर प्रधान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि घर पर रहने को अपराध कैसे बनाया जा सकता है. सीजेआई ने पूछा, क्या हम उनकी गिरफ्तारी का निर्देश दें? अगर कोई नागरिक मतदान करने नहीं जाता, तो हम क्या कर सकते हैं? पीठ ने अनिवार्य मतदान कानून की व्यावहारिक कठिनाइयों का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव के दिन कई नागरिक अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, अगर हम इसे स्वीकार कर लें, तो मेरे भाई न्यायमूर्ति बागची को कामकाजी दिन होने के बावजूद मतदान के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा. इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा, न्यायिक कार्य भी महत्वपूर्ण है. पीठ ने समाज के कमजोर वर्गों की चिंता भी जताई. उन्होंने कहा, अगर कोई गरीब व्यक्ति कहे कि मुझे अपनी मजदूरी कमानी है, मैं मतदान कैसे करूं? तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? याचिकाकर्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जो मतदान न करने वालों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव तैयार करे. इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमें आशंका है कि ये मुद्दे नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं.

सपा अध्यक्ष अखिलेश ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा

'नारी को नारा बनाने' की कोशिश कर रही भाजपा

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक के बहाने नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है. सपा प्रमुख ने महिला आरक्षण से संबंधित तीन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन भाजपाई चालबाजी के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा इस (महिला) आरक्षण को लेकर नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही. लेकिन जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनका मान-सम्मान कैसे रखेंगे. जिस मूल संगठन से आप

निकले हैं, उसमें मान-सम्मान के लिए कितनी नारी हैं? सपा सांसद ने कहा, हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा के अंदर जल्दबाजी क्यों है? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालनी चाहती है, वह जाति जनगणना को टालना चाहती है और ऐसा कर वह आरक्षण को टालना चाहती है. उन्होंने सरकार पर आधी आबादी में मुस्लिम महिलाओं को नहीं गिनने का आरोप लगाते हुए कहा, हमारी मांग है कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए. उन्होंने दावा किया कि भाजपा का असली लक्ष्य वोट हासिल करना और सत्ता में बने रहना है, इसलिए ये विधेयक लाये गए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा की यही राजनीतिक चाल है कि जब पुराने लोग समझ जाते हैं तो वे नये लोगों को लक्षित करते हैं, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश कन्नौज से सपा सांसद ने सत्तारूढ़ दल पर यह भी आरोप लगाया, भाजपा की कमीशन खोरी और चंदा वसूली की वजह से जो महंगाई बढ़ी है उससे उनकी (महिलाओं की) रसोई सूनी हो गई है.

हरिवंश के राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध चुने जाने की संभावना

नयी दिल्ली: मनोनीत सदस्य हरिवंश के राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध चुने जाने की संभावना है क्योंकि उनके पक्ष में पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए वहीं विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उपसभापति पद के लिए चुनाव शुक्रवार को सुबह 11 बजे होगा। हरिवंश का कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को चुनाव कराने की तारीख तय की है। चुनाव प्रस्तावों के नोटिस देने की अंतिम तिथि और समय बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे था। सूत्रों के अनुसार, हरिवंश के पक्ष में पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए जबकि विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। विपक्ष ने मोदी सरकार द्वारा सात वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं करने के विरोध में चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहला प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन एस फांग्नोन कोन्यक ने किया। दूसरा प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पेश किया और भाजपा सांसद बृजलाल ने इसका समर्थन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका भाजपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर और जद (यू) सांसद संजय कुमार झा ने समर्थन किया। एक अन्य प्रस्ताव रालोद सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पेश किया, जिसका शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने समर्थन किया। सूत्रों ने बताया कि निर्धारित समय तक विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उपसभापति पद के लिए चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। पूरी संभावना है कि नड्डा द्वारा प्रस्तुत और कोन्यक के समर्थन वाले पहले प्रस्ताव को सदन ध्वनि मत से पारित कर दे। सूत्रों ने बताया कि सभापति राधाकृष्णन उपसभापति पद के लिए हरिवंश के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद सदन के नेता और विपक्ष के नेता स्थापित परंपरा के अनुसार उन्हें आसन तक ले जाएंगे। हरिवंश दो बार सदन के उपसभापति रह चुके हैं और यदि निर्वाचित होते हैं, तो यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने इस मामले पर कोई सार्थक परामर्श भी नहीं किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हरिवंश 3.0 विपक्ष के सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। ''हरिवंश 3.0'' से तात्पर्य हरिवंश के तीसरे कार्यकाल से है। रमेश ने विपक्ष के विरोध के कारण बताते हुए कहा, पहला, मोदी सरकार ने सात वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा ''दूसरा, राज्यसभा में उपाध्यक्ष के समकक्ष उपसभापति होता है। हरिवंश का दूसरा कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हुआ। इसके एक दिन बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया और अब वह तीसरे कार्यकाल के लिए राजग के उम्मीदवार हैं। रमेश ने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विचार किया गया हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष के मन में हरिवंश के प्रति किसी भी तरह का अनादर नहीं है। हरिवंश का कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और उन्होंने 10 अप्रैल को शपथ ली।

वेतन निर्धारण नियमों के खिलाफ पूर्व सैनिकों की याचिका न्यायालय ने खारिज की

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पूर्व सैनिकों के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें मौजूदा वेतन-निर्धारण नियमों की वैधता को चुनौती दी गई थी। समूह का आरोप था कि मौजूदा ढांचा सेना के उन पूर्व सैनिकों को अनुचित रूप से दंडित करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद सिविल सेवाओं में शामिल होते हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जो बदले में यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता, जिनमें मुख्य याचिकाकर्ता बैद्य नाथ चौधरी भी शामिल हैं, असंतुष्ट हैं, तो वे अपनी शिकायतों के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) से संपर्क कर सकते हैं। चौधरी और पांच अन्य लोगों ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अश्विनी दुबे के माध्यम से दायर उनकी याचिका में केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 और उसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 1 मई, 2017 के ज्ञापन का हवाला दिया था।

अदालत में पेश हुए केजरीवाल, न्यायमूर्ति शर्मा से हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया

नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा से उनके अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने की अपील की। केजरीवाल ने हलफनामे में दावा किया है कि शराब नीति मामले में उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखने को लेकर न्यायाधीश शर्मा का 'प्रत्यक्ष रूप से हितों का टकराव' है। न्यायमूर्ति शर्मा ने रजिस्ट्री को पूर्व मुख्यमंत्री के हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने का निर्देश दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई से उनके अलग होने की मांग संबंधी केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह 'मामले की सुनवाई दोबारा शुरू नहीं कर रही हैं'। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए। सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी अपना लिखित जवाब दाखिल करेगी। केजरीवाल के अनुरोध पर अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को अपने जवाबों की एक प्रति उन्हें देने को कहा। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, लेकिन यह मामला सुरक्षित है। मैं इसे दोबारा नहीं खोल रही हूं। सुरक्षित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाता। केजरीवाल ने 14 अप्रैल के अपने अतिरिक्त हलफनामे में दावा किया कि न्यायाधीश के बच्चे केंद्र सरकार के सूचीबद्ध वकील हैं, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से काम मिलता है और वह सीबीआई की ओर से इस मामले में पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 'हितों का सीधा टकराव' है, जिससे उनकी आशंका को और बढ़ा दिया है, इसलिए न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष मामले को अपने से अलग करने का आधार बनता है। केजरीवाल ने अदालत में प्रस्तुत होकर दलील देने के लिए समय भी मांगा क्योंकि उन्हें आशंका है कि न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई जारी रहने से ''कानून द्वारा अपेक्षित न्यायिक निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तटस्थता'' का पूर्ण स्वरूप बरकरार नहीं रह जाएगा। केजरीवाल ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी सहित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति शर्मा के बेटे को काफी कानूनी कार्य सौंपा गया था। हलफनामे में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2023 में न्यायमूर्ति शर्मा के बेटे को कुल 2,487 मामले, 2024 में 1,784 मामले और 2025 में 1,633 मामले सौंपे गए थे। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इन 'महत्वपूर्ण तथ्यों' की जानकारी प्राप्त की और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा पैनल में शामिल करना मानद नहीं बल्कि इसमें अदालत में पेशी और वित्तीय लाभ शामिल हैं। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश के खिलाफ कई आपत्तियां उठाईं। इन आपत्तियों में यह भी शामिल है कि न्यायाधीश शर्मा ने पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें, मनीष सिसोदिया और के कविता सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर राहत देने से मना कर दिया था और 'कठोर व निर्णायक' निष्कर्ष भी दिए थे। मेहता ने न्यायमूर्ति शर्मा को सुनवाई से अलग करने की याचिका का विरोध किया और केजरीवाल व अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। मेहता ने केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं को 'अपरिपक्व आशंकाएं' बताते हुए अदालत से कहा कि यह 'संस्थागत सम्मान' का मामला है और न्यायमूर्ति शर्मा को दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 'बेबुनियाद आरोपों' पर उनका अलग होना एक गलत मिसाल कायम करेगा। अदालत ने न्यायमूर्ति शर्मा को सुनवाई से अलग करने की याचिका पर 13 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तमिलनाडु चुनाव: टीवीके का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। टीवीके प्रमुख विजय ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का कल्याण उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सभी वादों को पूरा किया जाएगा। साथ ही जो नहीं कहा है, वह भी करेंगे। चेन्नई के नुंगमबक्कम स्थित एक निजी होटल में गुरुवार को जारी घोषणापत्र में टीवीके ने महिलाओं को अपनी ओर खींचने के लिए कई वादे किए हैं। इसमें 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता देने की बात कही है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को साल में 6 रसोई गैस सिलेंडर, निर्धन परिवारों की मदद के लिए शादियों में आठ ग्राम सोना और दुल्हन को गुणवत्तापूर्ण सिल्क साड़ी देने का भी वादा किया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की बात भी इसमें शामिल है। टीवीके प्रमुख विजय ने घोषणापत्र में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का भी वादा किया है। पार्टी ने 100 कामराज स्तर के स्कूल, सभी जिलों में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले मुफ्त आवासीय स्कूल, प्रत्येक स्कूल में आधुनिक बुनियादी ढांचा और विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान किए जाने का वादा किया है। इसके अलावा प्रत्येक तमिल छात्र के शिक्षा सपनों को समर्थन देने के लिए स्नातक से पीएचडी तक 20 लाख रुपये तक ऋण की गारंटी का वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में नशामुक्त तमिलनाडु का वादा किया है। घोषणापत्र में एक परिवार को 25 लाख रुपये तक का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का वादा किया है। प्रत्येक नागरिक को वार्षिक जांच और सस्ती दवाएं प्रदान करने की बात भी कही है। टीवीके ने घोषणापत्र में कहा है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को 4,000 रुपये प्रति माह, 12वीं और आईटीआई-डिप्लोमा करे हुए युवाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के रूप में 25 लाख रुपये और सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक निश्चित समय सारिणी का वादा किया है। कृषि क्षेत्र के लिए टीवीके ने कहा है कि पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों के लिए कृषि सहकारी समितियों से लिए गए सभी फसल ऋण पूरी तरह माफ किए जाएंगे। पांच एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानों को कृषि सहकारी समिति के फसल ऋण पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। धान के लिए 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति टन न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि तेल फसल किसानों के लिए नारियल की कीमत स्थिर की जाएगी। पट्टेदार किसानों और कृषि मजदूरों को सीधे सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा।

जम्मू कश्मीर को मादक पदार्थों की बुराई से मुक्त कराने तक चैन से नहीं बैठूंगा : उपराज्यपाल

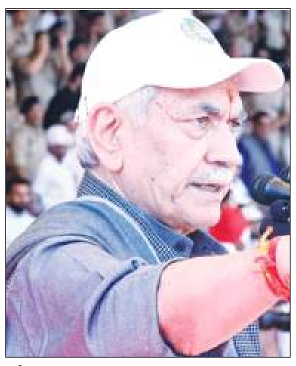

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस केंद्रशासित प्रदेश को वह मादक पदार्थों की बुराई से मुक्त नहीं करा लेते। उन्होंने यहां महिला किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे वह समाज कल्याण विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग, सभी नशा मुक्ति के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा, ''मैंने 11 अप्रैल को जम्मू में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया और हमने फैसला किया है कि जब तक हम नशीली दवाओं की बुराई को खत्म नहीं कर देते, हम आराम से नहीं बैठेंगे।'' उन्होंने कहा, ''जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2020 में 'नशा मुक्त भारत अभियान' शुरू किया था, तब जम्मू-कश्मीर में भी काफी प्रयास किए गए थे। पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है, अधिक मादक पदार्थ जब्त किये जा रहे हैं, पहले की तुलना में अधिक गिरफ्तारियां हो रही हैं और अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।'' सिन्हा ने कहा कि कई मई के पहले सप्ताह में कश्मीर में नशा विरोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''हम तीन मई को अभियान के कश्मीर संस्करण को शुरू करेंगे। मैं आप बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप आगे आएं और नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर बनाने में योगदान दें।'' उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार अकेले इस समस्या से पार नहीं पा सकती। उन्होंने कहा, ''हमने ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने मादक पदार्थों के व्यसन के चलते अपने बच्चे को खो दिया है या उनकी बेटी उसका शिकार हो गई है। हम इस खतरे से छुटकारा पा सकते हैं, यदि सरकार की शक्ति को लोगों के प्रयासों का समर्थन प्राप्त हो।'' उपराज्यपाल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और कृषि-उद्यमिता में महिला किसानों के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

चंडीगढ़ और पंजाब के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला

चंडीगढ़: चंडीगढ़ और पंजाब के बरनाला में बृहस्पतिवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल मिले। अधिकारियों ने कहा कि गहन जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बम की धमकियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते, श्वान दस्ते और एम्बुलेंस व दमकल विभाग सहित अन्य दलों को तुरंत स्कूलों में भेजा गया। पुलिस के अनुसार, बरनाला के छह स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिले थे। बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि धमकियों की सूचना मिलते ही विस्फोटक एवं सुरक्षा जांच दलों और संबंधित थाना पुलिस सहित सभी अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों की जांच की गई और स्कूलों के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया। पिछले कुछ हफ्तों में पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर इसी तरह की धमकियां मिली थीं, जो बाद में फर्जी निकलीं। ताजा घटनाक्रम उसी कड़ी का हिस्सा लग रहा है। कुछ दिन पहले पटियाला और मोगा के भी कई स्कूलों को ऐसी ही फर्जी बम की धमकी मिली थी।

उर्दू भाषा को लेकर फिरहाद हाकिम के बयान पर शुभेंदु अधिकारी की तीखी प्रतिक्रिया

कोलकाता: उर्दू भाषा को लेकर कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम की कथित टिप्पणी पर भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से बंगाल में अरब संस्कृति और उर्दू भाषा को बढ़ावा दे रही है, वह बंगाली और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें उर्दू भाषा से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में फिरहाद हाकिम के कथित तौर पर यह बयान दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल के 50 प्रतिशत लोग उर्दू में बात करें तो उन्हें खुशी होगी, जो स्वीकार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में एक वीडियो सामने आया है (हिन्दुस्तान समाचार इसकी पुष्टि नहीं करता), जिसमें फिरहाद हाकिम को इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना जा रहा है। इसी बयान को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक सुधांशु शेखर द्वारा दी इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड, एक्सप्रेस हाउस, एन एच 6 मौजा–प्रशस्थ व अंकुरहाटी, पोस्ट– सलप, थाना–डोमजूर, जिला–हावड़ा–711409 से मुद्रित एवं 19, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कोलकाता–700 007 से प्रकाशित। प्रधान संपादक : सुधांशु शेखर, प्रबंध कार्यालय : 19, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कोलकाता–700 007, RNI No. WBHIN/2007/22434 फोन : 9831494084, टेलीफैक्स : 22743382 ई–मेल : yuvashakti@hotmail.com प्रकाशन संबंधी समस्त विवादों का निपटारा कोलकाता न्यायालय के अधीन

मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 02 मई से 31 मई के बीच संपन्न किया जाएगा

युवा शक्ति न्यूज

गया : भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य बिहार राज्य में निर्धारित कार्यक्रमानुसार 02 मई 2026 से 31 मई 2026 के बीच संपन्न किया जाएगा।इस चरण में आम नागरिकों की सुविधा के लिए सेल्फ एनिमेरशन (स्व-गणना) का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।इच्छुक नागरिक 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 के बीच सेल्फ एनिमेरशन पोर्टल ह्रींींि://िश.लशपींीि.सेंीं.ळप पर लॉगिन कर अपने परिवार एवं मकान से संबंधित विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं।सेल्फ एनिमेरशन करने के उपरांत एक सेल्फ एनिमेरशन आईडी जनरेट होगी।नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस आईडी को सुरक्षित रखें एवं अपने घर आने वाले प्रगणक को उपलब्ध कराएं।प्रगणक द्वारा इस आईडी का मिलान उनके मोबाइल डिवाइस में उपलब्ध विवरण से किया जाएगा।मिलान उपरांत आवश्यकतानुसार जानकारी को सत्यापित एवं संपादित किया जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर परिवार से पूछकर डाटा में संशोधन भी किया जा सकता है।सेल्फ एनिमेरशन का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है।इस संबंध में जिले के डीएम शशांक शुभंकर ने सभी ज़िले के नागरिकों से अपील है कि वे सेल्फ एनिमेरशन का अधिक से अधिक उपयोग करें तथा जनगणना कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

अग्निमित्रा पाल ने गिनाई पिछले पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धियां

आसनसोल : आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने गुरुवार को भाजपा पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अपने पांच वर्षों के कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने कामकाज और विकास कार्यों को गिनाते हुए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा।भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी आसनसोल दक्षिण में कई ऐसे विकास कार्य किए, जो सत्ताधारी दल के विधायक नहीं कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक विकास के बजाय विधायक निधि का दुरुपयोग करते हैं, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी।उन्होंने कहा कि जब वह चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच जा रही हैं, तो उन्हें लोगों का समर्थन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्हें विश्वास है कि 23 अप्रैल

को मतदान के दिन आसनसोल दक्षिण की जनता एक बार फिर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी।

अग्निमित्रा पाल ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने कभी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया और हमेशा सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने हट्टन रोड पर टोटो चालकों द्वारा सड़क पर वाहन खड़ा करने से होने वाली यातायात समस्या का मुद्दा उठाया। इस पर मलय घटक द्वारा आपत्ति जताने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मिलकर टोटो के लिए अलग पार्किंग बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आपसी राजनीतिक विरोध के कारण वह योजना लागू नहीं हो सकी।उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के कारण न केवल आसनसोल बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि नेताओं को जनता की समस्याओं की चिंता नहीं है।भाजपा प्रत्याशी ने दामोदर नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा भी उठाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया कि विकास की बात करने के बावजूद अब तक इस दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए।अग्निमित्रा पाल ने कहा कि भाजपा केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने दावा किया कि देश के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है और डबल इंजन सरकार के कारण वहां तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और राज्य के विकास के लिए भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी है।उन्होंने आसनसोल दक्षिण की जनता से भाजपा को एक मौका देने की अपील करते हुए कहा कि अन्य दलों ने केवल वादे किए, जबकि भाजपा अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है।

भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष मिले नए सीएम से

युवा शक्ति न्यूज

गया : जिला भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पटना में मिलकर पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया।इन्होंने वर्षों से बनकर तैयार गया प्रेस क्लब को चालू कराने, पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराने, पत्रकारों को पेंशन और स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों की उपरोक्त समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुने और निदान कराने का आश्वासन दिए हैं।

सांसद शताब्दी रॉय ने तृणमूल उम्मीदवार हरे राम सिंह के समर्थन में जनसभा की

आसनसोल : जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार हरेराम सिंह के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यह जनसभा चुरूलिया हाट तल्ला में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से सांसद शताब्दी रॉय उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में हरेराम सिंह के साथ विश्वनाथ बाउरी, सुब्रत अधिकारी, शेख शानदार, प्रेमपाल सिंह, ब्रज नारायण राय, इंद्र बाध्यकर, लतीफा काजी, मृदुल चक्रवर्ती, राखी कर्मकार, प्रदीप मुखर्जी और शेख असरफ सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।इस अवसर पर हरेराम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2021 में उन्हें यहां की जनता का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव से पहले वह जामुड़िया के लोगों के बीच आए थे और उनसे को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तृणमूल को समर्थन देने की अपील की थी। जनता ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें पहली बार इस क्षेत्र से विजयी बनाया। उन्होंने कहा कि यह इलाका पहले वामपंथियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन जनता के सहयोग से तृणमूल को यहां जीत मिली।हरेराम सिंह ने आगे कहा कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और उन्होंने यह बात ममता बनर्जी से भी कही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कहा, ताकि अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य किए गए हैं और जो काम शेष हैं, उन्हें अगले कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जामुड़िया की जनता से समर्थन मांगा।सभा को संबोधित करते हुए शताब्दी रॉय ने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वे जनता की भावनाओं से खेलते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे असाजिक तत्वों से दूर रहने की अपील की और कहा कि मतदान विकास के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में बच्चों को निशुल्क शिक्षा, राशन और लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है। किसानों को भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि इन सभी विकास कार्यों को जारी रखने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल को ही समर्थन देना आवश्यक है। अंत में उन्होंने सभी से तृणमूल उम्मीदवार हरेराम सिंह के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया।

न्यूज कॉर्नर

जनता दरबार में आमजनों की शिकायतें सुनी गई

युवा शक्ति न्यूज

गया : जिले के एसएसपी सुशील कुमार के द्वारा जनता दरबार में आमजनों की शिकायतें सुनी गई।जिसमें फरियादी अपनी-अपनी समस्या लेकर उपस्थित हुए।एसएसपी के द्वारा सभी लोगों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना गया और उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

एमयू में छात्र समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से की मुलाकात, समाधान की मांग

युवा शक्ति न्यूज

बोधगया(गया) : मगध विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों को हो रही विभिन्न परेशानियों को विस्तार से रखते हुए उनके शीघ्र एवं प्रभावी समाधान की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि परीक्षा, पंजीयन, अंक प्रमाण पत्र, पीएच.डी. नामांकन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में हो रही देरी और अनियमितता के कारण छात्रों की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हो रही है।इस वजह से छात्रों के बीच असमंजस और चिंता की स्थिति बनी हुई है।राज्य यूनिवर्सिटी सह संयोजक मैक्स अवस्थी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित कदम उठाने चाहिए, ताकि शैक्षणिक वातावरण सुचारू रूप से संचालित हो सके।लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान होना आवश्यक है, जिससे छात्रों को राहत मिल सके।एसएफडी प्रांत संयोजक सूरज सिंह ने अपने विस्तृत बयान में कहा कि मगध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही है।उन्होंने कहा कि परीक्षा, पंजीयन, अंक प्रमाण पत्र एवं पीएच.डी. नामांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में समयबद्धता बेहद आवश्यक है।सूरज सिंह ने यह भी कहा कि यदि समय पर समाधान सुनिश्चित होता है, तो इससे न केवल छात्रों को राहत मिलेगी, बल्कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। छात्र सदैव संवाद और सहयोग के माध्यम से सकारात्मक बदलाव के पक्षधर रहे हैं।कुलपति ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रस्तुत सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।अंत में प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से आग्रह किया कि सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।इस मौके पर एसएफडी प्रांत संयोजक सूरज सिंह, राज्य विश्विद्यालय सह संयोजक मैक्स अवस्थी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन मिश्रा, शशि कुमार मौजूद रहे।

शब्दवीणा की साहित्यिक भेंटवार्ता एक शाम, साहित्य के उद्देश्यों पर हुई बातचीत

युवा शक्ति न्यूज

गयाजी : राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था शब्दवीणा की हरियाणा प्रदेश समिति एवं फरीदाबाद जिला समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मासिक साहित्यिक भेंटवार्ता एक शाम साहित्य के नाम के अप्रैल अंक का आयोजन हुआ।कार्यक्रम में बतौर आमंत्रित साहित्यकार हरियाणा की कवयित्री एवं इनर व्हील क्लब ऑफ साउथ-वेस्ट कोलकाता की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी सुमन माहेश्वरी रहीं।शब्दवीणा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रश्मि प्रियदर्शनी ने सुमन माहेश्वरी का शब्दवीणा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया।कार्यक्रम का संचालन एक शाम, साहित्य के नाम की संचालन प्रभारी कवयित्री रिया अग्रवाल ने एवं संयोजन शब्दवीणा की हरियाणा प्रदेश सचिव सरोज कुमार ने किया।वार्ताकार रिया अग्रवाल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमती माहेश्वरी ने अपने साहित्यिक एवं समाज सेवा से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने अत्यंत प्रेरक रचनाएँ पढ़ीं।कुशल मंच संचालन के लिए आवश्यक बातों पर चर्चा हुई।श्रीमती माहेश्वरी ने कहा कि उन्हें वर्ष 1996 में राष्ट्रपति भवन में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ था एवं तत्कालीन भारत की प्रथम महिला विमला शर्मा के हाथों उन्हें सम्मानित भी किया गया था।उन्होंने अपनी उन खट्टी-मीठी अविस्मरणीय यादों को भी साझा किया।विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपने जुड़ाव एवं उनसे प्राप्त अनुभूतियों एवं सीखों को साझा किया।श्रीमती माहेश्वरी ने अपने काव्य संग्रह भावों के मोती से अपनी रचनाएँ पढ़ीं।उनकी आशाओं के पंख लगा हम उड़ने-उड़ाने आये हैं।धरती पर उतरेगा स्वर्ग यह विश्वास दिलाने आये हैं।घर-घर में सच्चाई की गीता होगी।हर नारी प्रिय पावनी सीता होगी सुन कर दर्शकों एवं श्रोताओं से खूब वाहवाहियाँ मिलीं।महिला सशक्तीकरण पर भी उन्होंने प्रशंसनीय रचनाएँ पढ़ीं।श्रीमती माहेश्वरी ने साहित्य के साथ अध्यात्म एवं समाज सेवा को जोड़े जाने पर बल दिया।कहा कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए।साहित्य का उद्देश्य समाज में नकारात्मकता का अंत करके सकारात्मकता का सृजन करना होना चाहिए।ईर्ष्या-द्वेष जैसी निकृष्ट भावनाओं से ऊपर उठकर समाज के हित में कार्य करने कहा।उन्होंने डॉ रश्मि, श्रीमती सरोज, श्रीमती अग्रवाल के साथ समस्त शब्दवीणा परिवार के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शब्दवीणा केंद्रीय पेज से किया गया, जिससे जुड़कर सुरेश विद्यार्थी, दीपक कुमार, बबन बदिया, जैनेन्द्र कुमार मालवीय, पी. के. मोहन, सरिता कुमार, रश्मि बिनानी, अजय माहेश्वरी, श्रवण सहस्त्रांशु, रमेश चंद्र, अजय कुमार, अनुराग सैनी मुकुंद, आशा साहनी, रचना झा, डॉ विजय शंकर, संतोष कुमार जयंत सहित देश के विभिन्न प्रदेशों से जुड़े दर्शकों एवं श्रोताओं ने कार्यक्रम का आनंद उठाया।अपनी टिप्पणियों से अपनी भावनाएं एवं प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कीं।

डीएम ने दैनिक जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएँ

युवा शक्ति न्यूज

गया : जिले के डीएम शशांक शुभंकर ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित दैनिक जनता दरबार के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 50 आमजनों की समस्याएँ सुनीं।इस अवसर पर भूमि विवाद, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें, शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों समेत अन्य मामलों को लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष रखा।डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करें।इलेक्ट्रिक कार्य करने के लिये इलेक्ट्रिक लाइसेंस निर्गत करवाने के लिये अनुरोध किया है, डीएम ने विधुत कोषांग को निर्देश दिए हैं

उत्कल दिवस समारोह एनईपी 2020 की अवधारणा के अनुरूप : कुलपति

युवा शक्ति न्यूज

टेकारी(गया) : उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय परिसर में मनाए जाने वाली उत्कल दिवस का बहुआयामी औचित्य है।जहां एक तरफ उत्कल दिवस समारोह के आयोजन से विश्वविद्यालय में ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है वहीं ऐसे आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की अवधारणा को पूर्ण करते हैं।उक्त वक्तव्य दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) के कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह ने विश्वविद्यालय के ओड़िया शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा उत्कल दिवस एवं ओड़िया नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित उत्कलिका 2026 में कहीं।सीयूएसबी के मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रो के. एन. सिंह ने कहा कि उड़ीसा दिवस भारत की विविध संस्कृति और भारत की साझी विरासत का एक शानदार उदाहरण है।उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं, प्राध्यापक एवं कर्मियों के रूप में कार्यरत हैं जो अनुकरणीय है।मुझे प्रसन्नता है कि उड़ीसा के बच्चे बिहार के गयाजी में स्थित इस विश्वविद्यालय में केवल अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ ओडिशा की संस्कृति का संस्कार लेकर आए हैं जो इस परिसर को विविधता प्रदान करता है। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति महोदय ने उत्कल दिवस के आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए ओडिया छात्र - छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए काफी प्रशंसा की।कुलसचिव प्रो. नरेंद्र कुमार राणा ने स्वागत भाषण में कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य सिर्फ पठन - पाठन तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में चिंतन रचनात्मकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना भी है।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ओडिशा राज्य का गठन के भाषा आधार पर हुआ था उसी प्रकार एनईपी 2020 मातृभाषा और भाषाओं के शिक्षा के केंद्र में रखने पर बल देती है।ओडिशा की समृद्ध संस्कृति जैसी परंपराएं हमें इस दिशा में प्रेरणा प्रदान करती है, हमें अंतर शिक्षा के महत्व को समझने में सहायता करती है और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है।ओडिशा की आपदा प्रबंधन सतत विकास और सामाजिक समावेशन की उपलब्धियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिन्हे हम अपने शिक्षण में सम्मिलित कर सकते हैं।जन सम्पर्क पदाधिकारी (पीआरओ) मोहम्मद मुदस्सीर आलम ने गुरुवार को बताया कि उत्कल दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत के पश्चात कुलपति प्रो के. एन. सिंह, कुलसचिव प्रो नरेंद्र कुमार राणा, वित्ताधिकारी रश्मि त्रिपाठी, परीक्षा नियंत्रक डॉ. शांतिगोपाल पाइन एवं अन्य गणमान्यों ने ओडिशा की संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।इसके पश्चात स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के राज्य के रूप में निर्माण के एतिहासिक परिदृश्य के साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम की रुपरेखा को साझा किया।आगे छात्र - छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य एवं गीत प्रस्तुत किये

वीडब्ल्यूडीसी के माध्यम से संवेदनशील गवाहों की कराएं गवाही : प्रभारी प्रधान जिला जज

युवा शक्ति न्यूज

गया : संवेदनशील गवाहों की गवाही सफलतापूर्वक संवेदनशील गवाह बयान केंद्र (वीडब्ल्यूडीसी) के माध्यम से संपन्न कराने की दिशा में न्यायमंडल गया के प्रभारी प्रधान जिला जज सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शशिकांत ओझा की अध्यक्षता में गुरुवार को सिविल कोर्ट सभागार में बैठक की गयी।बैठक में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि वीडब्ल्यूडीसी के जरिये डरे सहमे गवाहों की गवाही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सकता है।इससे संवेदनशील गवाहों सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।प्रभारी प्रधान जिला जज ने कहा कि वीडब्ल्यूडीसी के जरिये गवाहों को डराने-धमकाने से बचाना व उन्हें न्याय प्रक्रिया में शामिल होने के अनुकूल माहौल देना है। बताया गया परिवार न्यायलय न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यौन अपराधों के पीड़ित या ऐसे व्यक्ति जिन्हें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक धमकी का सामना करना पड़ रहा हो।वैसे गवाह को एक अलग कमरे में बैठकर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गवाही ली जाएगी।जिससे उन्हें आरोपी का सामना न करना पड़े।वैसे गवाहों के लिए हीं वीडब्ल्यूडी सेंटर काफी सहयोगी सिद्ध होगा।मौके पर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शशिकांत ओझा एवं परिवार न्यायालय न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा, सचिव अरविंद कुमार दास के अलावा सभी न्यायिक पदाधिकारीगण मौजूद थें।

बिहार लोकल बॉडीज फेडरेशन द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया

युवा शक्ति न्यूज

गया :गयाजी नगर निगम के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ अज्ञात एवं तथाकथित व्यक्तियों द्वारा नगर निगम के सफाई कर्मियों को भ्रमित एवं उकसाने का प्रयास किया गया है. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त व्यक्ति न तो किसी मान्यता प्राप्त संगठन से जुड़े हैं और न ही किसी प्रकार के अधिकृत प्रतिनिधि या नेता हैं.इस संदर्भ में अध्यक्ष, बिहार लोकल बॉडीज फेडरेशन द्वारा लिखित रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया है और न ही वे इस पूरे प्रकरण में किसी भी रूप में सम्मिलित हैं.

इसके बावजूद तथाकथित असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ सफाई कर्मियों को गुमराह एवं उकसाया गया, जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम क्षेत्र में सफाई कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ.इस दौरान निगम अधिकारियों द्वारा संबंधित असामाजिक तत्वों से वार्ता भी की गई, जिसमें उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गईं, जैसे कि न्यूनतम वेतन 783 प्रतिदिन किया जाए, लंबे समय से कार्यरत सभी सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए तथा सफाई कर्मियों को कार्य हेतु आवश्यक वस्त्र (ड्रेस) उपलब्ध कराए जाएं.उक्त मांगों में से कुछ मांगें पूर्व से ही प्रक्रियाधीन हैं. उदाहरणस्वरूप, सफाई कर्मियों के लिए वस्त्र उपलब्ध कराने हेतु निविदा (टेंडर) की प्रक्रिया की जा चुकी है तथा बहुत ही जल्द सभी कर्मियों को वस्त्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे.साथ ही, निगम द्वारा कर्मियों के हित में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें अनुकंपा के आधार पर रिक्त पदों पर बहाली किया गया है, पारिवारिक पेंशन की प्रक्रिया चालू किया जा रहा है, छठे वित्त आयोग की अंतर राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा सभी कर्मियों को पहचान पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है.हालांकि, अन्य प्रमुख मांगें जैसे 783 न्यूनतम वेतन निर्धारित करना एवं कर्मियों का नियमितीकरण राज्य/बोर्ड स्तर से संबंधित विषय हैं, जिन पर नगर निगम द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना संभव नहीं है.

वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय भी बोर्ड स्तर का विषय है, जिस पर सशक्त समिति के चुनाव के उपरांत आगामी बैठक में विचार कर निर्णय लिया जाएगा.बुधवार की सुबह कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्थिति को और अधिक बिगाड़ने का प्रयास किया गया.इन तत्वों ने कुछ सफाई कर्मियों को भड़काकर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया, साथ ही नगर निगम कार्यालय में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की गई.

इस दौरान निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया, जो कि अत्यंत निंदनीय एवं दंडनीय कृत्य है.उक्त घटनाक्रम के आलोक में, संबंधित तथाकथित असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है.नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया ने सभी सफाई कर्मियों से अपील करता है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक बातों में न आएं तथा असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर कोई भी अनुचित कार्य न करें.

निगम प्रशासन उनके हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है.नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया ने बताया कि अफवाह फैलाने एवं उकसाने वाले तत्वों का किसी भी प्रकार से समर्थन न किया जाए.यदि किसी भी कर्मी द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कोई अनुचित कार्य किया जाता है, तो उनके विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.निगम यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने सभी कर्मियों की बात सदैव सुनता है.जिन कर्मियों को किसी प्रकार की समस्या हो, वे सीधे कार्यालय में आकर संबंधित अधिकारियों से मिलें.कृपया ऐसे असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अपने ही निगम के कार्यों को बाधित न करें एवं शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

पटना एवं मुजफ्फरपुर के बाद गया में कामकाजी महिला छात्रावास आकांक्षा-सह-सखी निवास का उद्घाटन

युवा शक्ति न्यूज

गया : महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षित आवासीय सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत गया में कामकाजी महिला छात्रावास (आकांक्षा-सह-सखी निवास) का उद्घाटन गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से किया गया।इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की सचिव-सह-प्रबंध निदेशक बंदना प्रेयषी द्वारा पटना से वर्चुअल माध्यम से छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया गया।उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गया में राज्य प्रतिनिधि कार्यक्रम प्रबंधक विनय एस पी सिंह एवं राज्य परियोजना प्रबंधक अंकिता कश्यप एवं ज़िला प्रतिनिधि डॉ रश्मि वर्मा ज़िला प्रोग्राम पदाधिकारी गया, नैना कुमारी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर गया एवं महिला एवं बाल विकाश निगम की परियोजना प्रबंधक, जयवन्ती सिन्हा, सुशांत आनंद विशाल कुमार वर्मा, आरती कुमारी केंद्र प्रशासक द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया।इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद् एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।यह छात्रावास राज्य सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एवं केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य

कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं किफायती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में सचिव-सह-प्रबंध निदेशक बंदना प्रेयषी ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं की सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में बढ़ती सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यस्थल के निकट सुरक्षित एवं सुलभ आवास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।इसी परिप्रेक्ष्य में इस छात्रावास की स्थापना की गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल है।छात्रावास में कुल 50 कामकाजी महिलाओं के आवास की व्यवस्था की गई है।यहां सुरक्षित आवास के साथ-साथ भोजन की सुविधा भी मात्र 3000 प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।यह सुविधा विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जो अपने गृह जिले से बाहर रहकर रोजगार प्राप्त कर रही हैं।उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास निगम एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व से ही पटना एवं मुजफ्फरपुर में इस प्रकार के छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं।गया में इस छात्रावास की स्थापना इस पहल का महत्वपूर्ण विस्तार है।छात्रावास के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था की गई है, जिसमें अधीक्षिका, उपाधीक्षिका, सुरक्षा कर्मी, रसोइया, बहुउद्देश्यीय कर्मी एवं सफाईकर्मी सम्मिलित हैं।उद्घाटन अवसर पर गया में उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह छात्रावास महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित करेगा।यह परियोजना महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।